सच बोलने की हिम्मत

राजधानी चौपाल

RNI No. HARHIN/25/A3341

अंक : 09 | वर्ष : 01 | साप्ताहिक (01 से 07 मार्च 2026) | पृष्ठ 8 | मूल्य : 5/- रुपये | E-mail : rajdhanichoupal@gmail.com

लगातार 12वीं बार जनता पर नहीं लगा कोई नया टैक्स, 'अंत्योदय' के संकल्प के साथ हर वर्ग को साधा; लाडो लक्ष्मी योजना में अब 1.80 लाख आय वाली महिलाएं भी शामिल

ऐतिहासिक और कर-मुक्त बजट: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गढ़ा 'विकसित हरियाणा' का रोडमैप; 2.23 लाख करोड़ का पिटारा खुला

चंडीगढ़/हिसार (राजधानी चौपाल)। हरियाणा के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को विधानसभा में प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा और समावेशी बजट पेश किया। वित्त मंत्री के रूप में अपने दूसरे बजट भाषण की शुरुआत उन्होंने गुरु नानक देव जी के पवित्र सिद्धांतों—'किरत कर, नाम जप, वंड छक'—से की, जो इस बजट की लोक-कल्याणकारी मंशा को साफ बयां करता है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पेश किए गए 2,23,653 करोड़ के इस बजट में न केवल विकास की रफ्तार को 10.28% बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है, बल्कि बिना किसी नए कर के समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का मान भी रखा गया है।

केसरिया सिख पगड़ी पहनकर सदन में पहुंचे मुख्यमंत्री ने अपने भाषण के दौरान गुरु रविदास, कबीरदास के दोहों और वसीम बरेलवी की शायरी के जरिए यह संदेश दिया कि उनकी सरकार मानवीय मूल्यों और तकनीकी प्रगति का अद्भुत संगम पेश कर रही है। बजट के केंद्र में 'लाडो लक्ष्मी' के जरिए नारी शक्ति और 'एग्री डिस्कॉम' के माध्यम से अन्नदाता को रखा गया है। 1 लाख युवाओं को AI की ट्रेनिंग देने का संकल्प हरियाणा को देश के तकनीकी मानचित्र पर अग्रणी बनाने की एक दूरदर्शी सोच है। यह बजट न केवल आंकड़ों का एक पुलिंदा है, बल्कि प्रदेश के सर्वांगीण विकास का एक जीवंत रोडमैप है, जो हर हाथ को काम और हर घर को सम्मान देने की गारंटी देता है।

इसके साथ ही, जीरकपुर-पंचकूला बाईपास और नए खेल स्टेडियमों का निर्माण बुनियादी ढांचे की मजबूती और युवाओं के सुनहरे भविष्य की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सरकार ने मध्यम वर्ग को करों से राहत देकर आर्थिक स्थिरता का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है।

बजट 2026-27 के मुख्य स्तंभ: राजधानी चौपाल की विशेष विश्लेषण रिपोर्ट

महिला सशक्तिकरण: लाडो लक्ष्मी योजना का ऐतिहासिक विस्तार

मुख्यमंत्री ने मातृशक्ति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए 'दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना' के दायरे को व्यापक बना दिया है।

- **आय सीमा में भारी वृद्धि:** अब 1 लाख के बजाय 1.80 लाख तक की सालाना आय वाले परिवारों की महिलाएं इस योजना के लिए पात्र होंगी।
- **लाभार्थियों का बढ़ता आंकड़ा:** इस घोषणा से लाभार्थियों की संख्या 8.62 लाख से बढ़कर 19.62 लाख हो जाएगी।
- **स्वास्थ्य सुरक्षा:** बेटियों के लिए मुफ्त HPV वैक्सीन और उपमंडल अस्पतालों में 'स्वस्थ नारी क्लीनिक' की स्थापना की जाएगी।
- **आर्थिक रियायतें:** महिलाओं के नाम वाहन पंजीकरण पर 1% टैक्स की छूट और कॉमर्शियल ईवी के लिए 10 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण।

अन्नदाता का कल्याण: 'एग्री डिस्कॉम' की स्थापना और भारी सब्सिडी

किसानों के लिए बजट में क्रांतिकारी बदलाव की घोषणा की गई है, जिससे खेती की लागत कम होगी और आमदनी बढ़ेगी।

- **नया बिजली निगम:** किसानों को त्वरित ट्यूबवेल कनेक्शन सुनिश्चित करने के लिए 'एग्री डिस्कॉम' नाम से अलग बिजली निगम बनेगा।
- **प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन:** रसायन मुक्त खेती अपनाने पर 10,000 प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि 5 साल तक दी जाएगी।
- **फसल विविधीकरण:** धान छोड़कर तिलहन या कपास उगाने वाले किसानों को 8,000 के अलावा 2,000 का अतिरिक्त बोनस मिलेगा।

युवा और तकनीक: एआई (AI) ट्रेनिंग से मिलेगा रोजगार का पंख

बेरोजगारी को मात देने के लिए सरकार ने युवाओं को आधुनिक कौशल से लैस करने का निर्णय लिया है।

- **1 लाख युवाओं को ट्रेनिंग:** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) क्षेत्र में 1 लाख युवाओं को तैयार किया जाएगा ताकि वे वैश्विक नौकरियों के लिए प्रतिस्पर्धी बन सकें।
- **मेक इन हरियाणा नीति:** स्थानीय युवाओं को रोजगार देने वाले उद्योगों को अब 48,000 के बजाय 1 लाख प्रति कर्मचारी वार्षिक सब्सिडी दी जाएगी।
- **खेलों को बढ़ावा:** 12 जिलों में 21 नए स्टेडियम और हर जिले में 'लघु खेलो इंडिया सेंटर' की स्थापना होगी।

गरीब और श्रमिक: आवास और मजदूरी में बड़ी राहत

सबका साथ, सबका विकास के नारे को चरितार्थ करते हुए बजट में गरीबों की बुनियादी जरूरतों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

- **छत की गारंटी:** प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 43 हजार नए घर, 20 हजार से अधिक प्लॉट और 8 हजार फ्लैट देने का लक्ष्य है।
- **न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि:** अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी को 11,257 से बढ़ाकर 15,200 करने की सिफारिश को लागू करने की तैयारी है।

शिक्षा क्षेत्र: डिजिटल भविष्य और सुरक्षा

- **मुफ्त सामग्री:** प्राइमरी स्कूलों के छात्रों को बैग, वर्दी और स्टेशनरी पूरी तरह मुफ्त मिलेगी।
- **विद्यार्थी सुरक्षा:** किसी अप्रिय हादसे में छात्र की मृत्यु पर 'बाल मेमोरियल इनिशिएटिव' के तहत 5 लाख की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
- **स्कूल इंफ्रा:** 1 नवंबर तक राज्य के सभी स्कूलों में ड्यूल डेस्क की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

हरियाणा बजट का गणित: लोक-लुभावन घोषणाओं और बढ़ते कर्ज के बीच झूलती प्रदेश की अर्थव्यवस्था

चंडीगढ़/हिसार (राजधानी चौपाल)। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा पेश किया गया वर्ष 2026-27 का बजट एक ओर जहाँ सामाजिक सुरक्षा और 'अंत्योदय' के संकल्प को दोहराता है, वहीं दूसरी ओर इसके भीतर छिपे आर्थिक आंकड़े भविष्य की चुनौतियों की ओर भी इशारा कर रहे हैं। 2.23 लाख करोड़ रुपये के इस विशालकाय बजट का विश्लेषण करें तो एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आता है—सरकार अपने खजाने का एक बड़ा हिस्सा 'फ्रीबीज' यानी मुफ्त की योजनाओं और पुराने कर्ज के ब्याज पर खर्च कर रही है, जिससे बुनियादी ढांचागत विकास (पूँजीगत व्यय) के लिए सीमित गुंजाइश बच रही है।

फ्रीबीज का भारी बोझ: 14 विभागों के बराबर पैसा मुफ्त योजनाओं में

राजस्व के बंटवारे में इस बार 'मुफ्त' की योजनाओं का बोलबाला रहा है। प्रदेश सरकार इस साल 22,304 करोड़ रुपये सामाजिक कल्याण की ऐसी योजनाओं पर खर्च करेगी, जिन्हें अर्थशास्त्री 'फ्रीबीज' की श्रेणी में रखते हैं। यह राशि कुल बजट का लगभग 10 प्रतिशत है। इस राशि की विशालता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यह प्रदेश के 14 महत्वपूर्ण विभागों (जिनमें गृह, सहकारिता, जेल, परिवहन, उद्योग, राजस्व और महिला एवं बाल विकास शामिल हैं) के संयुक्त बजट के बराबर है। सबसे बड़ा खर्च सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर हो रहा है, जिसके लिए 9,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके बाद 'दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना' आती है, जिसका बजट 1,500 करोड़ बढ़ाकर 6,500 करोड़ रुपये कर दिया गया है। बिजली सब्सिडी पर भी 6,021 करोड़ रुपये का भारी-भरकम बोझ खजाने पर पड़ेगा।

कर्ज का चक्रव्यूह: हर हरियाणवी पर 1.37 लाख रुपये का बोझ

बजट का दूसरा सबसे चिंताजनक पहलू बढ़ता कर्ज है। वर्तमान में हरियाणा पर 3.51 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है। सरकार अगले वित्त वर्ष में 40,293 करोड़ रुपये का नया कर्ज लेने की योजना बना रही है, जिससे कुल कर्ज 3.91 लाख करोड़ रुपये तक पहुँच जाएगा। पिछले 10 वर्षों में प्रदेश पर कर्ज का बोझ पौने तीन गुना बढ़ गया है। यदि इसे प्रदेश की 2.85 करोड़ की आबादी में बांटा जाए, तो हर नागरिक पर लगभग 1.37 लाख का कर्ज बैठता है। कर्ज से भी बड़ी समस्या उसका ब्याज चुकाना है। सरकार को अपनी अनुमानित राजस्व प्राप्ति (कमाई) का 15.6% हिस्सा यानी 29,266 करोड़ रुपये केवल ब्याज की अदायगी में खर्च करना होगा। यह ब्याज खर्च पिछले एक दशक में ढाई गुना बढ़ चुका है। जब कमाई का इतना बड़ा हिस्सा पुराने बोझ को उतारने में चला जाए, तो नई परियोजनाओं के लिए धन जुटाना सरकार के लिए टेढ़ी खीर साबित होता है।

वेतन और पेंशन का बढ़ता ग्राफ: बजट का 23% हिस्सा तय

सरकारी मशीनरी को सुचारू रूप से चलाने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन व पेंशन पर भी भारी खर्च हो रहा है। वित्त वर्ष 2026-27 में इस मद में 52,419 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है, जो कुल बजट का 23.4% है। गौरतलब है कि वर्ष 2017-18 में यह खर्च 26,037 करोड़ था, जो महज 10 साल में लगभग दोगुना हो गया है। प्रदेश में वर्तमान में 3.73 लाख सक्रिय कर्मचारी और 1.70 लाख पेंशनभोगी हैं, जिनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है, लेकिन यह राजस्व पर निरंतर दबाव बढ़ा रहा है।

फ्रीबीज, वेतन, पेंशन और ब्याज के अनिवार्य खर्चों के बाद सरकार के पास असली विकास कार्यों (जैसे नई सड़कें, बड़े पुल, सिंचाई परियोजनाएं और अस्पताल निर्माण) के लिए बहुत कम राशि बचती है। इस मद में केवल 28,205 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो कुल बजट का महज 12.6% है। यद्यपि पिछले वर्ष के मुकाबले इसमें 2.1% की मामूली वृद्धि हुई है, लेकिन जानकारों का कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए यह राशि पर्याप्त नहीं है। यही कारण है कि प्रदेश में कई बड़े प्रोजेक्ट्स शुरू होने के बाद बजट के अभाव में लेटलतीफी का शिकार हो जाते हैं। इन चुनौतियों के बीच एक सुखद पहलू यह है कि हरियाणा की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है।

पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की कोठी जलाने का मामला : जाट आरक्षण आंदोलन के 56 लोग सीबीआई कोर्ट से बरी

127 लोगों की हुई गवाही, चार जज, डीसी, दो एसपी भी शामिल

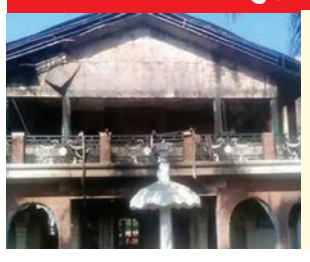

सीबीआई कोर्ट में चली सुनवाई के दौरान सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बयान दर्ज करने वाले चार जजों के अलावा तत्कालीन रोहतक डीसी डीके बेहरा सहित तत्कालीन रोहतक एसपी व सीबीआई एसपी तक के बयान दर्ज हुए। केस में तेजी लाने के लिए हाईकोर्ट ने हर सप्ताह सुनवाई की हिदायत दी थी। साथ ही तय किया था कि दिसंबर 2025 तक सुनवाई पूरी हो जाए। हालांकि, बाद में सुनवाई की समय सीमा बढ़ा दी थी। जिसमें आज फैसला आया है।

पंचकूला (राजधानी चौपाल)। जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान रोहतक में पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की कोठी जलाने के मामले में पंचकूला सीबीआई कोर्ट शुक्रवार को अपना निर्णय सुनाया है। बहुचर्चित केस में 56 आरोपी हैं, जिसमें ज्यादातर रोहतक व झज्जर के रहने वाले हैं। सीबीआई कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। सीबीआई कोर्ट में दाखिल आरोप पत्र के मुताबिक, पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के भतीजे रोहित के बयान पर साल 2016 में केंद्रीय जांच एजेंसी ने एफआईआर दर्ज की थी।

आरोप था कि जाट आरक्षण आंदोलन हिंसा के दौरान भीड़ लाठी, तलवार और पेट्रोल बम से लैस होकर दिल्ली बाइपास की तरफ से पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की कोठी की तरफ आई और जबरन घर में घुस गई। घर के अंदर खड़े वाहनों को आग लगा दी और कोठी का सामान लूट लिया। घर में मौजूद लोगों को मारने के इरादे से पेट्रोल बम फेंके।

आग लगने से हुआ था करोड़ों का नुकसान : इससे कोठी में आग लग गई और करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। पहले स्थानीय पुलिस ने जांच की, लेकिन बाद में सरकार ने केस सीबीआई को सौंप दिया था। सीबीआई की तरफ से आरोप पत्र दाखिल किया जिसमें 60 लोगों को आरोपी बनाया गया। इसमें अशोक बल्हारा, राहुल दादू, मनोज दूहन, जगपाल उर्फ जग्गा, धर्मेंद्र हुड्डा व अन्य शामिल हैं। जिसमें से तीन लोगों की मौत हो चुकी है तथा एक पीओ घोषित है।

कैप्टन कोठी जलाने में इन्हें बनाया था आरोपी : कैप्टन अभिमन्यू की कोठी जलाने के केस में सीबीआई ने मोहित, विजेंद्र सिंह राजेश कुमार, जोगेंद्र, समुंद्र, राहुल दादू, महेंद्र सिंह, सुदीप कलकल, जगपाल सिंह, नरेंद्र, मनोज दुहन, अभिषेक, धमेंद्र, सुमित, नसीब, योगानंद, विकास, दीपक, सुमित, प्रदीप, रविंद्र, अजय, दिलावर, प्रदीप, मोहित, कुलबीर फौगाट, हरिओम, विक्की, विरेंद्र, अमित, प्रदीप, अश्विनी, लक्ष्य, राहुल, अंकित, संदीप, जसबीर, भुवन सिंह, योगेश राठी, संदीप राठी, अरविंद गिल, बिजेंद्र सिंह, जितेंद्र राठी, राहुल हुड्डा, सुमित मलिक, विजयदीप पंघाल, गौरव हुड्डा, अशोक बल्हारा, सचिन दहिया, सत्यवान कादियान, पवन हुड्डा, गौरव बुधवार, अनिल कुमार, अजय, सोमबीर, देवेंद्र, रविंद्रकांत, भगवान, सुमित दांगी व देवेंद्र धनखड़ का नाम शामिल हैं।

बजट 2026-27: 'मिलेनियम सिटी' को मिली विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी की सौगात; उद्योग विभाग के बजट में 47% का भारी उछाल, 'वेड इन इंडिया' का केंद्र बनेगा गुरुग्राम

गुरुग्राम (राजधानी चौपाल)| मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को विधानसभा में वित्त मंत्री के रूप में वर्ष 2026-27 का राज्य बजट पेश करते हुए प्रदेश की आर्थिक राजधानी गुरुग्राम के लिए विकास का नया अध्याय लिख दिया है। शहर की बढ़ती आबादी और ट्रैफिक की भीषण समस्या को केंद्र में रखते हुए मुख्यमंत्री ने न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खजाना खोला, बल्कि 'वेडिंग सिटी' जैसी अभिनव योजना के जरिए निवेश और रोजगार के नए द्वार भी खोल दिए। उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह ने इस बजट को 'विकसित हरियाणा' की नींव करार देते हुए कहा कि गुरुग्राम अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की औद्योगिक और सेवा क्षेत्र की धुरी बनेगा।

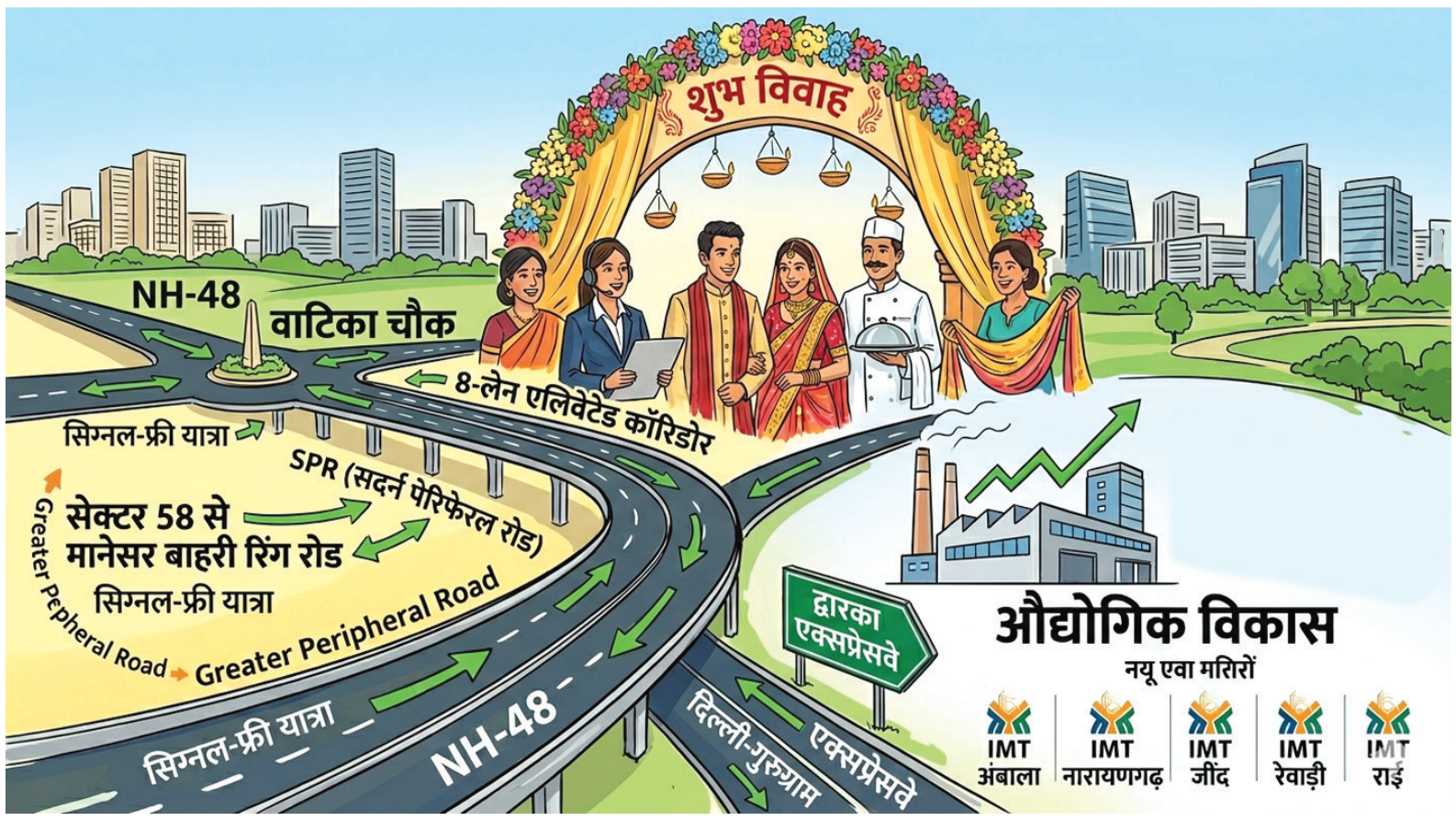

वेडिंग सिटी: सगाई से विदाई तक का नया वैश्विक गंतव्य

गुरुग्राम के लिए इस बजट की सबसे चर्चित और दूरगामी घोषणा 'वेडिंग सिटी' की स्थापना है। मुख्यमंत्री ने 'वेड इन इंडिया' की अवधारणा को हरियाणा की धरती पर उतारते हुए गुरुग्राम को एक समर्पित वेडिंग हब बनाने का ऐलान किया। यह केवल एक स्थान नहीं, बल्कि एक ऐसा इकोसिस्टम होगा जहां विवाह से जुड़े तमाम आयोजन—सगाई, मेहंदी, संगीत और मुख्य समारोह—एक ही परिसर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ संपन्न हो सकेंगे।

गुरुग्राम पहले से ही अपनी ऊंची इमारतों, लग्जरी रिसॉर्ट्स और विशाल बैंक्वेट हॉल्स के लिए दुनियाभर में प्रसिद्ध है। नई वेडिंग सिटी के आने से यहाँ का पर्यटन और सेवा क्षेत्र नई ऊंचाइयों को छुएगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इस परियोजना का उद्देश्य डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए विदेश जाने वाले भारतीयों को स्वदेश में ही विश्वस्तरीय विकल्प देना है। गुरुग्राम की सफलता के बाद ऐसी ही वेडिंग सिटी खरखौदा और पिंजौर में भी विकसित की जाएंगी।

रोजगार की नई लहर: युवाओं और महिलाओं को विशेष अवसर

वेडिंग सिटी केवल चमक-धमक तक सीमित नहीं है, बल्कि यह रोजगार सृजन का एक बड़ा इंजन साबित होगी। राजधानी चौपाल के विश्लेषण के अनुसार, इस योजना से इवेंट मैनेजमेंट, कैटरिंग, इंटीरियर डेकोरेशन, फोटोग्राफी और लॉजिस्टिक्स से जुड़े व्यवसायों को जबरदस्त बूस्ट मिलेगा।

विशेष रूप से महिलाओं के लिए इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं पैदा होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वेडिंग इंडस्ट्री एक 'मल्टी-बिलियन डॉलर' उद्योग है और गुरुग्राम को इसका केंद्र बनाकर हम हजारों स्थानीय युवाओं को सम्मानजनक रोजगार प्रदान करेंगे। इससे छोटे स्टार्टअप और स्थानीय कारीगरों को भी अपनी प्रतिभा दिखाने का वैश्विक मंच मिलेगा।

ट्रैफिक से मुक्ति: सेक्टर 58 से मानेसर तक ग्रेटर पेरिफेरल रोड

गुरुग्राम की सबसे बड़ी दुखती रग 'ट्रैफिक जाम' है। मुख्यमंत्री ने इसे गंभीरता से लेते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर ऐतिहासिक घोषणाएं की हैं। शहर की बाहरी कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए सेक्टर 58 से मानेसर तक एक नई 'बाहरी रिंग रोड' के निर्माण का प्रोजेक्ट शुरू होगा।

यह मार्ग शहर के आंतरिक ट्रैफिक को बायपास करने में मदद करेगा। जो वाहन दिल्ली या फरीदाबाद से मानेसर और जयपुर की ओर जाते हैं, उन्हें शहर के बीच से गुजरने की जरूरत नहीं होगी। इससे दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे (NH-48) पर वाहनों का दबाव 30% तक कम होने का अनुमान है, जिससे दैनिक यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी।

SPR का कायाकल्प: सिग्नल-फ्री यात्रा का सपना होगा साकार

सदर्न पेरिफेरल रोड (SPR) गुरुग्राम की लाइफलाइन मानी जाती है, लेकिन बढ़ते ट्रैफिक ने यहाँ रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। बजट 2026-27 में SPR को पूरी तरह सिग्नल-फ्री बनाने के लिए मेगा प्रोजेक्ट्स की घोषणा की गई है।

वाटिका चौक से घाटा गांव: इस खंड पर 8-लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा। यह कॉरिडोर शहर के प्रमुख चौराहों के ऊपर से गुजरेगा, जिससे वाटिका चौक से द्वारका एक्सप्रेसवे तक की यात्रा बिना किसी रुकावट के पूरी हो सकेगी।

एलिवेटेड स्ट्रेच और क्लोवरलीफ: SPR पर प्रस्तावित क्लोवरलीफ जंक्शन ट्रैफिक फ्लो को सुचारू बनाएगा, जिससे गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड और सोहना रोड के बीच की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। NH-48 से वाटिका चौक: मुख्यमंत्री ने NH-48 से वाटिका चौक तक 5.1 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण की भी घोषणा की है। इन परियोजनाओं पर करोड़ों रुपये खर्च किए जाएंगे, जो गुरुग्राम के इंफ्रास्ट्रक्चर को अगले स्तर पर ले जाएंगे।

उद्योग विभाग के बजट में भारी वृद्धि: 'औद्योगिक क्रांति' का आगाज

उद्योग मंत्री और बादशाहपुर के विधायक राव नरबीर सिंह ने बजट भाषण के बाद कहा कि यह बजट केवल आंकड़ों का मायाजाल नहीं, बल्कि एक विजनरी दस्तावेज है। मुख्यमंत्री ने उद्योग विभाग के बजट में 46.93 प्रतिशत की ऐतिहासिक वृद्धि करते हुए 1950.92 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

राव नरबीर सिंह ने तर्क दिया कि कोई भी राष्ट्र केवल कृषि के भरोसे विकसित देशों की श्रेणी में नहीं आ सकता। उन्होंने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां बड़े कृषि फार्म होने के बावजूद औद्योगिक विकास को ही उन्नति का आधार बनाया गया। मुख्यमंत्री का यह बजट हरियाणा को कृषि प्रधान राज्य से ऊपर उठाकर 'औद्योगिक पावरहाउस' बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

नई औद्योगिक टाउनशिप (IMT): हरियाणा का नया औद्योगिक नक्शा

बजट में औद्योगिक आधारभूत ढांचे को ग्रामीण और पिछड़े इलाकों तक ले जाने की योजना भी शामिल है। पिछले वर्ष की 10 नए IMT की घोषणा पर काम शुरू हो चुका है:

- **अंबाला और नारायणगढ़:** यहाँ भूमि खरीद की प्रक्रिया अंतिम चरण में है।
- **तोशाम, जींद, रेवाड़ी और राई:** इन क्षेत्रों में नई औद्योगिक टाउनशिप के लिए 'ई-भूमि' पोर्टल पर किसानों और भू-मालिकों से प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं।
- राव नरबीर सिंह ने विश्वास जताया कि ये नए औद्योगिक केंद्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में गुरुग्राम की धुरी को और मजबूत करेंगे और पूरे प्रदेश में संतुलित विकास सुनिश्चित करेंगे।

मिलेनियम सिटी से ग्लोबल हब की ओर

राजधानी चौपाल की विशेष रिपोर्ट के अनुसार, बजट 2026-27 गुरुग्राम की कायाकल्प करने वाला है। जहाँ 'वेडिंग सिटी' शहर को एक नई सांस्कृतिक और व्यापारिक पहचान देगी, वहीं फ्लाईओवर और एलिवेटेड कॉरिडोर का जाल शहर की रफ़्तार को बढ़ाएगा। सरकार का यह बजट स्पष्ट संदेश देता है कि गुरुग्राम न केवल हरियाणा की आर्थिक राजधानी बना रहेगा, बल्कि वर्ष 2047 के 'विकसित भारत' के संकल्प में अग्रणी भूमिका निभाएगा।

बजट हाइलाइट्स (गुरुग्राम):

- **वेडिंग सिटी:** 'वेड इन इंडिया' प्रोजेक्ट के तहत भव्य निर्माण।
- **एलिवेटेड कॉरिडोर:** NH-48 से वाटिका चौक (5.1 किमी)।
- **रिंग रोड:** सेक्टर 58 से मानेसर तक नई बाहरी कनेक्टिविटी।
- SPR **अपग्रेड:** वाटिका चौक से घाटा गांव तक 8-लेन एलिवेटेड रोड।
- **इंडस्ट्रियल फंड:** 1950.92 करोड़ रुपये का प्रावधान।

पानी के बिल पर सरचार्ज माफ करने की घोषणा

गुरुग्राम (राजधानी चौपाल)| हरियाणा के बजट में आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए पानी और सीवर बिल पर लगने वाला सरचार्ज माफ करने की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री की इस घोषणा से नगर निगम क्षेत्र के करीब 1700 उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। निगम के अनुसार पानी-सीवर बिलों पर लगभग 120 करोड़ रुपये बकाया है।

सरकार के फैसले के बाद उन उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, जिन पर लंबे समय से बकाया राशि के साथ सरचार्ज जुड़ता जा रहा था। अब सरचार्ज माफी से मूल राशि जमा कर खातों को नियमित कराया जा सकेगा। नगर निगम अधिकारियों का मानना है कि इस कदम से बकाया वसूली में तेजी आएगी और उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ कम होगा। सरकार ने बजट में घोषणा की है कि 31 मार्च 2025 तक जिन लोगों पर लाखों रुपये का संपत्तिकर बकाया है, उनके ब्याज को माफ करने का फैसला किया है। गुरुग्राम निगम में करीब एक लाख संपत्ति धारकों पर 200 करोड़ रुपये से अधिक का टैक्स बकाया है।

गुरुग्राम-ग्रेनो नमो भारत रूट पर काम होगा तेज

फरीदाबाद/गुरुग्राम (राजधानी चौपाल)| नोएडा-गुरुग्राम नौकरी करने वाले लाखों लोगों के लिए राहत की खबर है। हरियाणा सरकार ने सोमवार को बजट सत्र में नोएडा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को जोड़ने वाली नमो भारत ट्रेन (आरआरटीएस) के नए अलाइनमेंट को आधिकारिक मंजूरी दे दी है। यह ट्रेन ग्रेटर नोएडा, दिल्ली, गुरुग्राम और फरीदाबाद से होते हुए नोएडा एयरपोर्ट तक पहुंचेगा।

इस महात्वाकांक्षी परियोजना के लिए सरकार ने 3573 करोड़ रुपये का शुरुआती फंड मंजूर किया है, जिससे परियोजना पर जल्द कार्य शुरू होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों मेरठ में नमो भारत रैपिड रेल के शुभारंभ किया था। इसके साथ ही फरीदाबाद के लोगों की उम्मीदें काफी बढ़ गईं। इस महत्वाकांक्षी योजना की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार हो गई है। सोमवार को पेश बजट में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रूट के अलाइटमेंट को मंजूरी प्रदान की। परियोजना के पहले चरण में नोएडा-ग्रेटर नोएडा और गुरुग्राम के रास्ते फरीदाबाद को जोड़ने की योजना है। इस रूट के विकसित होने से रोजाना हजारों यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा, जो नौकरी, व्यापार और शिक्षा के लिए इन शहरों के बीच सफर करते हैं।

वर्तमान में इन मार्गों पर सड़क यातायात का भारी दबाव है। नमो भारत ट्रेन शुरू होने से यात्रा समय में बड़ी कमी आएगी और सड़कों पर वाहनों का दबाव भी घटेगा। परियोजना के तहत नमो भारत ट्रेन का 64 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर तैयार किया जाएगा। अलाइनमेंट के अनुसार, यह रूट फरीदाबाद और गुरुग्राम के प्रमुख हिस्सों को कवर करते हुए नोएडा एयरपोर्ट तक का सफर बेहद कम समय में तय करेगा।

आधुनिक सुविधाएं होंगी

परियोजना के तहत नमो भारत ट्रेन पूरी तरह आधुनिक तकनीक पर आधारित होगी। इसमें अत्याधुनिक कोच, स्वचालित सिग्नलिंग सिस्टम, बेहतर सुरक्षा व्यवस्था और यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस स्टेशन बनाए जाएंगे। ट्रेन की अधिकतम गति करीब 180 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। परियोजना के तहत फरीदाबाद में बाटा और बड़खल दो स्टेशन बनाए जाएंगे।

न्यूज ब्रीफ

बदमाशों ने कारोबारी के परिवार को बंधक बनाकर कैश व जेवरात लूटे

फरीदाबाद (राजधानी चौपाल)| मोहना क्षेत्र में शनिवार देर रात चार नकाबपोश बदमाशों ने पिस्तौल के बल पर कारोबारी के परिवार को बंधक बनाकर लूटपाट की। घटना रात करीब दो बजे हुई। कारोबारी प्रवीण पत्नी के साथ प्रथम तल पर सो रहे थे, जबकि भूतल पर उनके पिता वीरपाल और मां कृष्णा थे। बदमाश दरवाजे का शीशा निकालकर घर में घुसे। एक के पास पिस्तौल, दो के पास रॉड और एक के पास पाइप थी। उन्होंने दंपती को बंधक बनाकर अलमारियां खंगाली और सोने-चांदी के जेवर व 8 हजार रुपए लूट लिए। बदमाश ने भी फायरिंग की, लेकिन प्रवीण बच गए। पुलिस जांच में जुटी है।

कैंटीन ठेकेदार की हत्या में शामिल आरोपी गिरफ्तार, 5 दिन के रिमांड पर

गुरुग्राम (राजधानी चौपाल)| गुरुग्राम में कैंटीन ठेकेदार संजय शर्मा की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने रेकी करने वाले पांच हजार रुपए के ईनामी आरोपी को सोहना से गिरफ्तार किया है। नूंह के आटा गांव निवासी मनविंदर उर्फ मूली (34 वर्ष) ने ही संजय शर्मा की कार में कार से टक्कर मारी थी और संजय शर्मा की रेकी भी की थी। रेकी करने के लिए मनविंदर ने मुख्य आरोपी से 10 लाख रुपए भी लिए थे। मनविंदर उर्फ मूली पर पुलिस ने 5 हजार रुपए का ईनाम घोषित कर रखा था। हत्या की वारदात 6 जनवरी की सुबह सेक्टर-डी बसई गांव के पास की है। संजय शर्मा (55 वर्ष) डीपीजी ग्रुप ऑफ कॉलेज के बाहर कैंटीन चलाते थे। परिवार ने आरोप लगाया था कि 5 जनवरी को कैंटीन के बाहर कुछ युवकों का झगड़ा हुआ था। सीसीटीवी फुटेज न देने पर उन्होंने संजय को धमकी दी थी। अगले दिन सुबह पुलिस व संजय शर्मा के परिजनों को उसकी कार के एक्सीडेंट की सूचना मिली थी। पुलिस ने संजय शर्मा को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया था। मामले में सेक्टर-10 थाना पुलिस ने केस दर्ज कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनकी पहचान शर्मा शर्मा के मौसेरे भाई गुरुदत्त शर्मा उर्फ बालेश्वर शर्मा (56 वर्ष) निवासी गांव डहकोरा, जिला रोहतक व अनिल (48 वर्ष), निवासी गांव कंडोरा, जिला बागपत (उत्तर प्रदेश) के रूप में हुई।

कार की टक्कर से किसान की मौत

गुरुग्राम (राजधानी चौपाल)| तेज रफ्तार कार की टक्कर से 66 वर्षीय किसान की मौत हो गई। हादसा शनिवार दोपहर खरखड़ी रोड पर शराब के ठेके के पास हुआ। पुलिस ने अज्ञात चालक के खिलाफ आईएमटी मानेसर थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गांव कासन निवासी नरेश कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि एक मार्च 2026 को वह अपने चाचा 66 वर्षीय धर्मसिंह के साथ खेत से काम कर घर लौट रहे थे। धर्मसिंह आगे-आगे चल रहे थे और नरेश लगभग 100 कदम पीछे थे। करीब 12:30 बजे जब वे शराब के ठेके के पास पहुंचे, तभी गांव की ओर से बेकाबू सफेद रंग की ब्रेज़ा कार लापरवाही से धर्मसिंह को टक्कर मार कर चालक फरार हो गया।

सिंचाई विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारी से 13 लाख ठगे

गुरुग्राम (राजधानी चौपाल)| सिंचाई विभाग के एक सेवानिवृत्त अधिकारी के साथ निवेश के नाम पर करीब 13 लाख रुपये की ठगी होने का मामला सामने आया है। थाना साइबर अपराध मानेसर ने केस दर्ज किया है। मूलरूप से रोहतक के सेक्टर-14 के मकान नंबर 289 निवासी सत्यबीर गर्ग फिलहाल सेक्टर-82 स्थित वाटिका इंडिया नेक्स्ट में अपने बेटे के साथ रह रहे हैं। उन्होंने शिकायत में बताया कि पांच जनवरी को उनके मोबाइल पर एक व्हाट्सऐप नंबर से मैसेज आया। यह मैसेज एंकर इनवेस्टर के नाम से रुपये निवेश करने के बारे में था। उन्होंने रुचि जताई तो आईआईएफएल कैपिटल सर्विसेज से अमृता नामक युवती ने उन्हें बताया कि निवेश करने पर 95 प्रतिशत शेयर मिलते हैं। अमृता ने उनका डायरेक्ट मार्किट एक्सेस अकाउंट खुलवा दिया। उसने बैंक खातों में 13 ट्रांजेक्शन के माध्यम से करीब 13 लाख रुपये जमा करवा दिए। उसे डायरेक्ट मार्किट एक्सेस अकाउंट में 57 लाख रुपये दिखने लगे। जब उन्होंने अमृता से बात करके शेयर बेचने के बारे में कहा तो उसने बताया कि निवेश की गई राशि अभी पर्याप्त नहीं है। इस पर उन्हें संदेह हुआ तो केस दर्ज करवाया।

ग्वाल पहाड़ी क्षेत्र में पेयजल की आपूर्ति होगी

गुरुग्राम (राजधानी चौपाल)| इस साल दिसंबर तक गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड पर विकसित ग्वाल पहाड़ी क्षेत्र में पेयजल सप्लाई होगी। गुरुग्राम-महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) ने पाइप लाइन डालने के लिए एक ठेकेदार को टेंडर आवंटित कर दिया है।

निर्माणाधीन बूस्टिंग स्टेशन पर मशीनरी लगाने को लेकर टेडर जल्द जारी किया जाएगा। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने 20 साल पहले ग्वाल पहाड़ी विकास योजना तैयार की थी। इसके तहत आठ रिहायशी सोसाइटी और कॉलोनी विकसित करने के लिए लाइसेंस जारी किए हैं। सैकड़ों लोगों ने इन रिहायशी सोसाइटी और कॉलोनियों में रहना शुरू कर दिया है, लेकिन यह पानी के लिए पूर्णतया भूजल पर आश्रित हैं। इनमें वैली व्यू एस्टेट, सनसिटी आदि शामिल हैं। इस योजना में शामिल गांव पुरानी ग्वाल पहाड़ी, न्यू ग्वाल पहाड़ी, बंधवाड़ी, बालियावास, बलौला आदि गांव भी पानी के लिए भूजल पर आश्रित हैं। जीएमडीए की तरफ से इस क्षेत्र तक पानी पहुंचाने के लिए गांव ग्वाल पहाड़ी में 19 एमएलडी (मिलियन लीटर प्रतिदिन) क्षमता का बूस्टिंग स्टेशन तैयार किया जा रहा है। पिछले सप्ताह एक कंपनी को पाइप लाइन डालने के लिए करीब एक करोड़ रुपये का टेंडर आवंटित किया है। जीएमडीए की तरफ से इस ठेकेदार कंपनी को पाइप उपलब्ध करवाए जाएंगे। वहीं, बूस्टिंग स्टेशन पर मशीनरी लगाने के लिए जीएमडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीसी मीणा ने करीब चार करोड़ रुपये की डीपीआर को मंजूरी प्रदान कर दी है।

इसके तहत अगले सप्ताह तक टेंडर जारी कर दिए जाएंगे। इस काम को पूरा होने में करीब आठ महीने का समय लगेगा। दिसंबर से इस क्षेत्र को पेयजल उपलब्ध हो जाएगा। करीब 15 साल पहले हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) ने ग्वाल पहाड़ी तक पानी पहुंचाने की योजना बनाई थी। इसके तहत पाइप लाइन डालना शुरू किया था, लेकिन पाइप लाइन डालने का विरोध ग्रामीणों ने किया था। इस वजह से यह काम बीच में अटक गया था।

जीएमडीए के मुताबिक सेक्टर-72 के बूस्टिंग स्टेशन से ग्वाल पहाड़ी के बूस्टिंग स्टेशन तक पानी पहुंचाया जाएगा। इसके बाद पेयजल का वितरण किया जाएगा। बंधवाड़ी कूड़ा घर की वजह से आसपास गांवों के भूजल पर पर्यावरणविद् सवाल उठा चुके हैं। पर्यावरणविदों का आरोप है कि भूजल प्रदूषित हो चुका है। यह पीने के लायक नहीं है। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जांच में भी पानी के नमूने सही नहीं मिले हैं। जीएमडीए के कार्यकारी अभियंता अभिनव वर्मा ने बताया कि दिसंबर तक ग्वाल पहाड़ी क्षेत्र में पेयजल की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। बूस्टिंग स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है। पाइप लाइन का टेंडर आवंटित किया जा चुका है।

गुरुग्राम और फरीदाबाद में कूड़े से बिजली बनेगी

गुरुग्राम (राजधानी चौपाल)| शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने गुरुग्राम, फरीदाबाद और हिसार में वेस्ट-टू-एनर्जी (कचरे से बिजली बनाने वाले) प्लांट स्थापित करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इसके लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित की गई है, जो अगले 20 दिनों में विस्तृत रिपोर्ट और आरएफपी (रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल) तैयार कर मुख्यालय को सौंपेगी। सरकार ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए अनुभवी आईएएस अधिकारियों की टीम बनाई है, जिसमें गुरुग्राम, फरीदाबाद और हिसार के नगर निगम आयुक्तों के साथ अतिरिक्त आयुक्त भी शामिल हैं। कूड़े से बिजली बनाने के प्लांट लगने से शहर में कूड़े के ढेरों से राहत मिलेगी। प्रदूषित हवा से लोगों को राहत मिलेगी। गुरुग्राम में कचरे से बिजली बनाने की योजना पिछले करीब 10 वर्षों से केवल कागजों में सीमित रही है। बंधवाड़ी लैंडफिल साइट पर कूड़े के पहाड़ लगातार बढ़ते रहे, जिससे पर्यावरण और जनस्वास्थ्य पर गंभीर खतरा मंडराता रहा। वर्ष 2017 में निगम ने एक निजी कंपनी के साथ करार किया था, लेकिन जमीन खाली कराने और पुराने कचरे के निस्तारण को लेकर विवाद के चलते परियोजना आगे नहीं बढ़ सकी।

मिट्टी से भरे बेकाबू डंपर की टक्कर से महिला की मौत

गुरुग्राम (राजधानी चौपाल)| घर के बाहर कूड़ा डालने के लिए निकली एक महिला को मिट्टी से भरे डंपर ने टक्कर मार दी। खून से लथपथ हालत में महिला को अस्पताल में दाखिल करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस सिलसिले में थाना राजेंद्रा पार्क में मामला दर्ज हुआ है।

गांव चंदू के मकान नंबर 44 निवासी पवन कुमार ने पुलिस में शिकायत दी कि ग्राम पंचायत ने घरों से कूड़ा उठाने के लिए ट्रैक्टर ट्राली लगाई हुई है। शनिवार को ट्रैक्टर ट्राली उसके घर के बाहर आकर रुकी थी। उसकी पत्नी 31 वर्षीय पूनम रानी कूड़ा डालने के लिए घर से बाहर निकली थी। ट्रॉली के पीछे खड़ी होकर कूड़ा डाल ही रही थी कि इतने में चंदू-बादली रोड से तेजी गति से मिट्टी से भरा डंपर आया और ट्रैक्टर ट्राली में पीछे से टक्कर मार दी।

ड्रोन से सर्वे कराकर 42 गांवों में अवैध निर्माण गिराने की तैयारी

जीएमडीए से बिना अनुमति लिए मकानों, दुकानों और वेयर हाउस का निर्माण किया

गुरुग्राम (राजधानी चौपाल)| गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) के अधीन आ रहे 42 गांवों में ड्रोन से सर्वे कराकर अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने की तैयारी की जा रही है। इसमें सामने आए अवैध निर्माण को नोटिस दिया जाएगा। हर महीने ड्रोन सर्वे होगा। नए अवैध निर्माण को पनपने से रोका जाएगा। इन गांवों में करीब 250 अवैध निर्माण की पहचान की जा चुकी है।

जीएमडीए के अधीन गुरुग्राम ब्लॉक के गांव बुढेड़ा, साढराणा, चंदू, हमीरपुर, टीकली, अकलीमपुर, गैरतपुर बास, मांकडोला आते हैं, जबकि मानेसर में ग्वालियर, हसनपुर, बिनौला, बिलासपुर, पथरेड़ी, चांदला डूंगरवास, लांगड़ा, उदयपुरी, बाघनकी, खेड़की, सकतपुर आते हैं। इसके अलावा फर्रुखनगर ब्लॉक में सुल्तानपुर, कालियावास, सैदपुर मोहम्मदपुर, खेंटावास, धानावास, बाबरा बाकीपुर, ख्वासपुर, बासलांबी, खरखड़ी, मोकलवास, फकरपुर, सांपका, जमालपुर, ततारपुर, जटौला, जुडौला, ताजनगर, फाजिलपुर बादली, मुबारिकपुर, पातली हाजीपुर, इकबालपुर, झांझरौला और सरबसीपुर आते हैं। जीएमडीए को सूचना मिली है कि इन गांवों में अवैध रूप से कुछ कॉलोनियां काटी जा रही हैं। इसके अलावा जीएमडीए से बिना अनुमति लिए मकानों, दुकानों और वेयर हाउस का निर्माण किया जा रहा है।

इसको लेकर जीएमडीए ने फैसला लिया है कि इन गांवों का ड्रोन से सर्वे करवाया जाएगा। इस सर्वे के बाद मौके का निरीक्षण किया जाएगा। जहां-जहां अवैध निर्माण हुए हैं, वहां पर जमीन की पैमाइश करने के बाद जमीन या मकान मालिक को कारण बताओ नोटिस जारी किए जाएंगे। जहां अवैध निर्माण चल रहे हैं, उन्हें रूकवाया जाएगा। नए निर्माण को पनपने नहीं दिया जाएगा। हर महीने इन गांवों में ड्रोन सर्वे करवाया जाएगा।

सुल्तानपुर में अवैध रूप से फार्म हाउस बने: सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी के पांच किमी दायरे में किसी भी तरह का निर्माण बिना मंजूरी के नहीं किया जा सकता है। अधिकारियों के संज्ञान में आया है कि इस दायरे में कुछ लोगों ने फार्म हाउस, होटल और ढाबे बना लिए हैं। सर्वे के बाद इन्हें नोटिस जारी करने की तैयारी की जा रही है।

250 अवैध निर्माण की पहचान हुई: जीएमडीए ने इन गांवों में 250 अवैध निर्माण की पहचान की है। इन्हें नोटिस दिए जा रहे हैं। नोटिस मिलने के 15 दिन में इन्हें जवाब दाखिल करना है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर इन अवैध निर्माणों को मलबे में मिलाया जाएगा। इन अवैध निर्माण में 90 प्रतिशत दुकानों और वेयर हाउस का निर्माण हुआ है। अब जीएमडीए इन्हें जल्द गिरा सकता है।

सीएलयू लेकर निर्माण कर सकते हैं

जीएमडीए के अधीन 42 गांव आते हैं। अवैध निर्माण को लेकर यहां ड्रोन सर्वे करवाने का फैसला लिया है। करीब 250 अवैध निर्माण की पहचान की गई है। इन्हें नोटिस दिए जा रहे हैं। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर इन्हें तोड़ने की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। अवैध निर्माण को वैध करवाने के लिए सीएलयू के लिए आवेदन कर सकते हैं।

जीएमडीए डीटीपी के आरएस बाठ ने बताया कि गांवों में कृषि योग्य भूमि पर किसी भी तरह का निर्माण नहीं किया जा सकता है। यदि कृषि भूमि पर किसी तरह का निर्माण करना है तो उसके लिए जीएमडीए से सीएलयू करवाना होगा। इसके बाद नक्शे मंजूर करवाकर निर्माण करना होगा। इस तरह निर्माण करके लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी। बिना मंजूरी के निर्माण करने से तोड़फोड़ का डर बना रहेगा। लोगों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा।

बजट 2026-27: 'स्टील सिटी' हिसार को मिला सौगातों का 'आसमान', हांसी बनेगा नया औद्योगिक हब, 200 बेड अस्पताल और मिनी सचिवालय

हिसार/हांसी (राजधानी चौपाल) |

हिसार/हांसी (राजधानी चौपाल ब्यूरो): मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा में पेश किए गए वर्ष 2026-27 के राज्य बजट ने पश्चिमी हरियाणा के प्रवेश द्वार कहे जाने वाले हिसार जिले और ऐतिहासिक उपमंडल हांसी की तस्वीर बदलने की नींव रख दी है। 'विकसित हरियाणा-विकसित भारत' के विजन पर आधारित इस बजट में हिसार को न केवल एक औद्योगिक राजधानी के रूप में पहचान दी गई है, बल्कि हांसी को भविष्य के प्रशासनिक और व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए खजाना खोल दिया गया है। बजट भाषण में हिसार के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट) को केंद्र में रखते हुए इसके चारों ओर 'एयरो सिटी' और 'इंडस्ट्रियल कॉरिडोर' के निर्माण के लिए 1,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वहीं, हांसी के नागरिकों की वर्षों पुरानी मांग को ध्यान में रखते हुए यहाँ एक अत्याधुनिक मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल और नई अनाज मंडी के विस्तार की घोषणा की गई है।

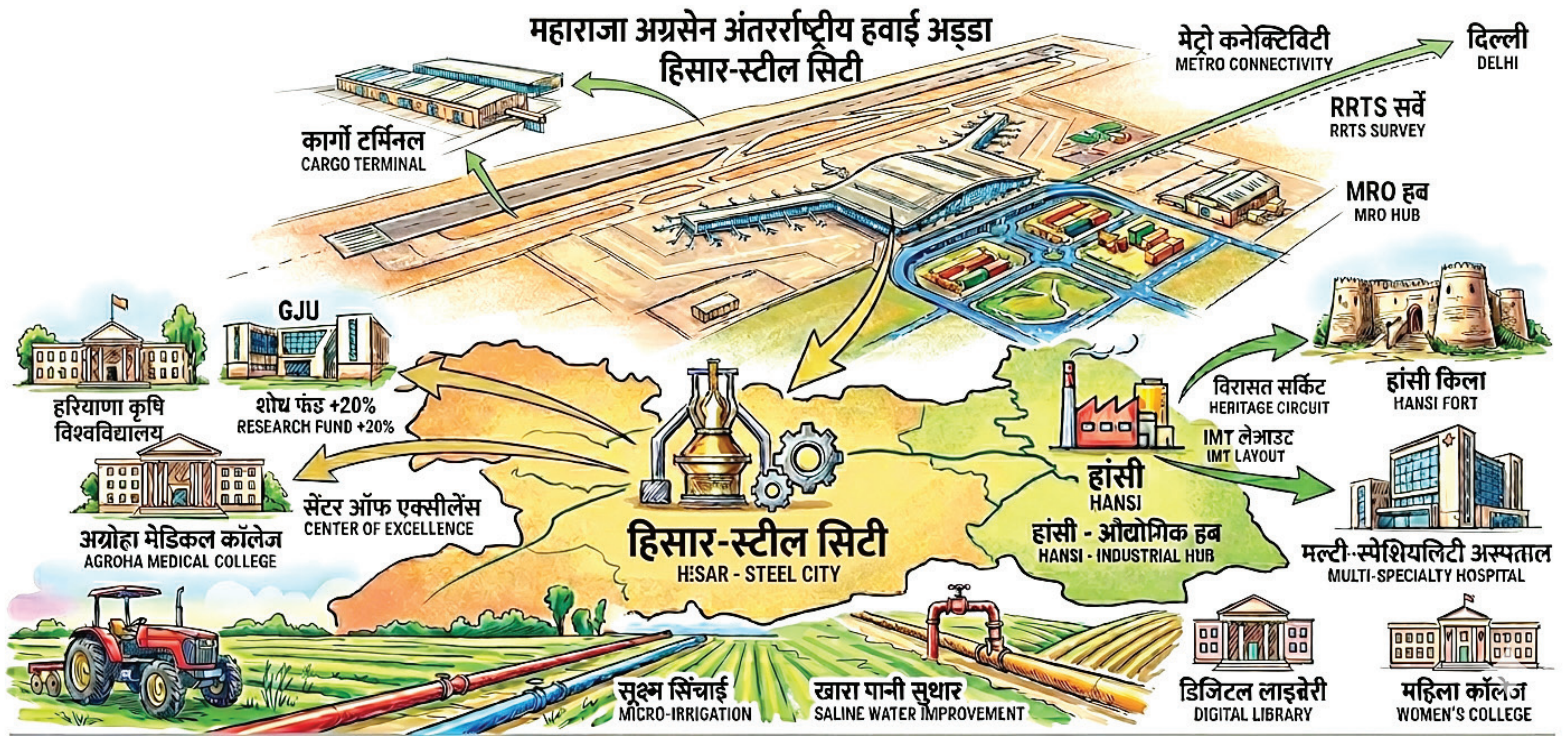

हिसार: विमानन और कनेक्टिविटी का नया वैश्विक केंद्र

बजट 2026-27 में हिसार जिले के लिए सबसे बड़ी घोषणा 'मेट्रो कनेक्टिविटी' और 'रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम' के सर्वे को लेकर रही। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि दिल्ली-रोहतक-हिसार कॉरिडोर को अब धरातल पर उतारने का समय आ गया है। इस परियोजना के लिए सरकार ने विशेष बजट आवंटित किया है जो इसे एनसीआर के साथ सीधा और तेज लिंक प्रदान करेगा।

- **महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट और एयरोट्रोपोलिस :** हिसार हवाई अड्डे को केवल एक रनवे तक सीमित न रखकर इसे 'एयरोट्रोपोलिस' के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके तहतः
- **कार्गो टर्मिनलः** उत्तर भारत का सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल हिसार में बनेगा, जिससे हिसार के स्टील और गारमेंट उद्योग को सीधा वैश्विक बाजार मिलेगा।
- **MRO हबः** विमानों की मरम्मत और रखरखाव (MRO) के लिए विशेष जोन स्थापित होगा, जिससे करीब 5,000 युवाओं को तकनीकी रोजगार मिलेगा।
- **एयरो सिटीः** हवाई अड्डे के पास आवासीय और वाणिज्यिक परिसरों का निर्माण किया जाएगा, जिससे हिसार में पर्यटन और रियल एस्टेट को भारी उछाल मिलेगा।

शिक्षा और स्वास्थ्यः अग्रोहा से हिसार तक बदलेगी तस्वीर

बजट में हिसार को शिक्षा और स्वास्थ्य के 'सुपर हब' के रूप में स्थापित करने के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं:

- **अग्रोहा मेडिकल कॉलेजः** इसे 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' बनाने के लिए 250 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यहाँ कैंसर और हृदय रोगों के लिए विशेष विंग स्थापित की जाएगी।
- **विश्वविद्यालयों को मजबूतीः** चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय (HAU) और गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (GJU) के लिए शोध फंड में 20% की ऐतिहासिक वृद्धि की गई है।
- **फ्लाईओवर और इंफ्रास्ट्रक्चरः** शहर की ट्रैफिक समस्या से निजात दिलाने के लिए राजगढ़ रोड और दिल्ली रोड पर दो नए फ्लाईओवर का प्रस्ताव बजट में शामिल है। साथ ही शहर की सभी मुख्य सड़कों के सौंदर्यीकरण के लिए 100 करोड़ रुपये का अलग से प्रावधान किया गया है।

ऐतिहासिक घोषणाः 'मॉडल जिला' बनेगा हांसी, विकास के लिए खुला सरकारी खजाना

हरियाणा के राजनीतिक मानचित्र पर अपनी विशिष्ट पहचान रखने वाले हांसी के लिए वर्ष 2026-27 का बजट ऐतिहासिक सौगातें लेकर आया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए हरियाणा के 23वें जिले के रूप में हांसी को एक 'अत्याधुनिक मॉडल जिले' के रूप में विकसित करने का भव्य ऐलान किया है। इस घोषणा के साथ ही हांसी के पूर्ण प्रशासनिक सशक्तिकरण का रास्ता साफ हो गया है।

प्रशासनिक आत्मनिर्भरता पर जोर

मुख्यमंत्री ने सदन को आश्वस्त किया कि वर्ष 2026-27 की शुरुआत तक हांसी में सभी जिला स्तरीय विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित कर दी जाएगी। सरकार का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों का विकेंद्रीकरण करना है, ताकि स्थानीय नागरिकों को अपने छोटे-बड़े कामों के लिए हिसार के चक्कर न लगाने पड़ें।

मॉडल जिले की मुख्य आधारशिलाएं:

- **मिनी सचिवालयः** सभी सरकारी विभागों को एक छत के नीचे लाने के लिए भव्य मिनी सचिवालय भवन का निर्माण होगा।
- **स्वास्थ्य विस्तारः** मौजूदा स्वास्थ्य ढांचे को मजबूती देते हुए 200 बेड का आधुनिक जिला अस्पताल बनाया जाएगा।
- **पुलिस बुनियादी ढांचाः** सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए अत्याधुनिक पुलिस लाइन और पुलिसकर्मियों हेतु आवासीय परिसर का निर्माण किया जाएगा।

ग्रामीण विकास और कृषि क्षेत्र

- **सिंचाईः** बालसमंद और आदमपुर क्षेत्र के लिए 'सूक्ष्म सिंचाई नहर नेटवर्क' के विस्तार के लिए 80 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- **खारा पानी सुधारः** हांसी और बरवाला बेल्ट में भूमिगत जल के खारेपन की समस्या को दूर करने के लिए 'वर्टिकल ड्रेनेज सिस्टम' और पायलट आधार पर 'डी-सेलिनेशन प्लांट' लगाए जाएंगे।
- **पशुपालनः** हिसार के पशुधन फार्म में 'भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक' केंद्र की स्थापना, जिससे हरियाणा की नस्ल सुधारने में मदद मिलेगी।

युवाओं और महिलाओं के लिए सौगातें

बजट में युवाओं के लिए हिसार में एक नया 'कौशल विकास केंद्र' और 'डिजिटल लाइब्रेरी' खोलने की बात कही गई है।

हांसी में छात्राओं की सुविधा के लिए एक नया राजकीय महिला महाविद्यालय खोला जाएगा। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं के स्वरोजगार के लिए हिसार जिले को 40 करोड़ रुपये की विशेष ऋण सब्सिडी दी जाएगी।

अशांति फैलाने वालों से निपटेगी पुलिस, 28 जगह नाकाबंदी

हिसार (राजधानी चौपाल)| होली और फाग पर अशांति फैलाने वाले लोगों से हिसार पुलिस सख्ती से निपटेगी। शहर से लेकर गांवों तक में पुलिस की प्रभावी गश्त रहेगी। यहां तक की संवेदनशील इलाकों व प्रमुख चौराहों पर नाकाबंदी करके कानून तोड़ने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। 28 जगह नाकाबंदी करके साइलेंसर से पटाखे बजाने व साइलेंसर निकालकर ध्वनि प्रदूषण फैलाने वालों, शराब पीकर वाहन चलाने वालों सहित लापरवाही से वाहन चलाकर दूसरों की जान को खतरे में डालने वाले रडार पर रहेंगे। ट्रैफिक पुलिस एल्को सेंसर से लैस होगी। रंग की आड़ में महिलाओं व युवतियों से छेड़छाड़ की घटनाओं पर मनचलों के विरुद्ध महिला पुलिस बल कार्रवाई करेगी। दंगा व आपात स्थिति में एक कंपनी पुलिस लाइन में मुस्तैद रहेगी। सभी थाना और चौकी प्रभारियों को एसपी हिसार ने निर्देश दिए हैं कि कानून और शांति व्यवस्था बिगाड़ने वाले को चिह्नित करके सख्ती से निपटा जाए। पीसीआर व डायल 112 की टीमें सूचना प्राप्त होने पर मौके पर पहुंचेंगी। सभी थानों में एचएचओ के साथ पर्यवेक्षण अधिकारी नियुक्त रहेंगे। इसके अलावा आधा-आधा प्लाटून का पुलिस बल व आधा-आधा सेक्शन का महिला पुलिस बल थाना शहर, थाना एचटीएम, थाना सिविल लाइन में हाजिर रहेगा। एसपी शशांक कुमार सावन ने अपील करते हुए कहा कि आमजन से होली-फाग पर कानून व्यवस्था की पालना करें। पुरानी रंजिश में नुकसान पहुंचाने की मंशा रखने वालों की सूचना पुलिस को जरूर दें। बिना किसी द्वेष, भेदभाव के रंगों के त्यौहार का आनंद लें। आपात स्थिति में डायल 112 पर कॉल करें।

आमजन, किसान और युवाओं सहित प्रत्येक वर्ग के लिए कल्याणकारी साबित होगा प्रदेश का बजट : गंगवा

हिसार (राजधानी चौपाल)| लोक निर्माण एवं जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा प्रदेश का बजट अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला बजट है, जिसमें गरीब कल्याण से लेकर उद्योगों को बढावा देने के प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा 2,23,658.17 करोड़ रुपये का यह बजट प्रस्ताव में आमजन, किसान और युवाओं सहित प्रत्येक वर्ग के लिए कल्याणकारी साबित होगा। कैबिनेट मंत्री ने जनस्वास्थ्य विभाग के संशोधित अनुमान 5469.22 करोड़ रुपये को 8.10 प्रतिशत से बढ़कर 5912.02 करोड़ रुपये करने के प्रस्ताव का स्वागत करने हुए कहा कि इस निर्णय से हरियाणा में स्वच्छ पेयजल और सीवरेज व्यवस्था और अधिक सुधार होगा। इसके अतिरिक्त लोक निर्माण विभाग के बजट अनुमान को भी 22 प्रतिशत से बढ़ाकर वर्ष 2026-27 में 5893.66 करोड रुपए करने का प्रस्ताव किया गया है। बजट में ग्रामीण क्षत्रों की उन्नति, शहरी आधुनिकीकरण रोजगार सृजन, कौशल विकास, स्टार्टअप प्रोत्साहन, इन्फ्रास्ट्रक्चर विस्तार व सामाजिक सुरक्षा के अनेक प्रावधान किए गए हैं। ग्रामीण उत्पादों की सीधी बिक्री हेतु ग्रामीण मंडियां की स्थापना से किसानों के साथ-साथ स्थानीय उद्यमियों को भी अपने उत्पादों की बिक्री में सहूलियत होगी। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के अंतर्गत मिलने वाले मुआवजे को 40000 रुपये प्रति एकड़ से बढ़ाकर 50000 रुपये प्रति एकड़ करने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की किसान हितेषी सोच को दर्शाता है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि हिसार में 30 करोड़ रुपए की लागत से हरियाणा पशु चिकित्सा महामारी विज्ञान केंद्र की स्थापना का निर्णय पशुपालकों के लिए महत्वपूर्ण है।

किसान हितैषी बजट, लाभान्वित होंगे कृषि से जुड़े आयाम : प्रो. काम्बोज

हिसार| हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. बीआर काम्बोज ने हरियाणा सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट को किसान हितैषी बताते हुए कहा कि यह बजट प्रदेश के किसानों की आय बढ़ाने व उत्पाद बेचने, कृषि लागत कम करने तथा आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। बजट में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से 2 हजार एकड़ के एक क्लस्टर में आधुनिकतम तकनीकों द्वारा स्मार्ट एग्रीकल्चर नाम से एक नई योजना द्वारा प्राकृतिक खेती शुरू करने का प्रस्ताव है। इसमें यदि किसानों को किसी प्रकार का भी नुकसान होगा तो उसकी हर पाई की भरपाई हरियाणा सरकार द्वारा की जाएगी। लवणीय भूमि को पुनर्जीवित किए जाने के लिए 1 लाख 40 हजार एकड़ भूमि को खेती लायक किया जाना। मेरा पानी मेरी विरासत योजना के अंतर्गत 10 हजार प्रति एकड़ अतिरिक्त बोनस दिया जाएगा। प्राकृतिक व जैविक किसानों को कृषि उपज बेचने के लिए मंडियों में जगह उपलब्ध करवाई जाएगी। गन्ना प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत किसानों को 3 हजार प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर 5 हजार प्रति एकड़ किया जाएगा।

बॉक्सर नवीन 'बूरा-सिरोही रत्न' से सम्मानित

हिसार (राजधानी चौपाल)| सर्व बूरा-सिरोही खाप का 13वां स्थापना दिवस सोमवार को कालियावास गांव में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन सर्व कालियावास गांव की ओर से किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे।

समारोह में खाप के राष्ट्रीय प्रधान रणवीर सिंह बूरा (किरमच) की मौजूदगी में घिराय निवासी इंटरनेशनल बॉक्सर नवीन बूरा को 'बूरा-सिरोही रत्न' सम्मान से

नवाजा गया। हरियाणा की सर्व बूरा-सिरोही गोत्र पंचायत की ओर से उन्हें यह विशेष सम्मान प्रदान किया गया। वहीं कालियावास ग्राम पंचायत की तरफ से भी शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। मंच का संचालन अजीत खरकड़ी ने किया। कार्यक्रम में नवीन बूरा अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम के कारण उपस्थित नहीं हो सके। उनकी ओर से उनके पिता जयवीर सिंह बूरा ने सम्मान ग्रहण किया।

गौरतलब है कि 19 फरवरी को नवीन बूरा ने गोरखपुर निवासी सिमरन के साथ विवाह किया और बिना दहेज शादी कर समाज के सामने मिसाल पेश की। इसी सामाजिक पहल को देखते हुए उन्हें यह सम्मान दिया गया। शादी की रस्मों में मिले 11,000 रुपये भी उन्होंने पंचायत को सप्रेम भेंट किए।

जीजेयू में शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट कोर्स फ्रेंच एवं जर्मन- ए-1 व ए-2 स्तर के ऑनलाइन आवेदन की तिथि 18 मार्च तक बढ़ाई

हिसार (राजधानी चौपाल)| जीजेयू के अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विभाग द्वारा संचालित शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट कोर्स-फ्रेंच एवं जर्मन ए-1 तथा ए-2 स्तर के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 18 मार्च 2026 कर दी गई है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. नरसी राम बिश्नोई ने बताया कि इन कोर्सों का उद्देश्य विद्यार्थियों को विदेशी भाषाओं में दक्षता प्रदान करना है, ताकि वे वैश्विक स्तर पर रोजगार, उच्च शिक्षा एवं प्रतिस्पर्धी क्षेत्रों में बेहतर अवसर प्राप्त कर सकें। आज के वैश्वीकरण के दौर में फ्रेंच एवं जर्मन जैसी भाषाओं का ज्ञान तकनीकी, पर्यटन, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, दूतावासों तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विभागाध्यक्षा डॉ. प्रियंका सिंगला ने जानकारी दी कि ए-1 स्तर का कोर्स 90 घंटे तीन माह तथा ए-2 स्तर का कोर्स 110 घंटे 3.5 माह का है। ए-2 स्तर के लिए ए-1 प्रमाणपत्र अनिवार्य है। प्रवेश प्रथम आओ-प्रथम पाओ के आधार पर किया जाएगा। सफल अभ्यार्थियों को विश्वविद्यालय की ओर से प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा, जो उनके बायोडाटा को और सशक्त बनाएगा। इच्छुक अभ्यार्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट WWW.GJUST.AC.IN पर 18 मार्च 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन हेतु कोई पंजीकरण शुल्क नहीं है।

भामाशाह नगर में होली परिवार मिलन समारोह मनाया गया

हिसार (राजधानी चौपाल)| भामाशाह नगर वेलफेयर सोसाइटी ने सोसाइटी के अध्यक्ष सत्य काम आर्य की अध्यक्षता में होली परिवार मिलन समारोह हर्ष और उल्लास के साथ मनाया। इसमें रमेश शर्मा, सुभाष मित्तल, आलोक आर्य, अनुराग मित्तल, दिपेश बंसल आदि का भरपूर सहयोग रहा। 100 से अधिक सदस्यों ने उपस्थित होकर एकता व भाईचारे का संदेश दिया।

समारोह के दौरान 13 प्रस्तुतियां पेश की गई। तंबोला, संगीत, नृत्य आदि का सभी ने भरपूर आनंद लिया। सोसाइटी के अध्यक्ष सत्य काम आर्य ने बताया कि भामाशाह नगर वेलफेयर सोसाइटी का यह 22वां प्रोग्राम था। सभी सदस्य पारस्परिक चंदन तिलक लगा कर सप्रेम से मिले। फूलों की वर्षा ने सबका मन मोह लिया। मंच संचालन रेशम खरबंदा व रम्मी गुप्ता ने किया व प्रतियोगिता संचालन उमेश गुप्ता ने किया। इस अवसर पर रामचंद्र गुप्ता, नरेंद्र जैन, सुनील गोयल, प्रदीप सराफ, पवन मित्तल, गुलशन खरबंदा, शकुंतला आर्य, सीमा शर्मा आदि वरिष्ठ नागरिक भी उपस्थित रहे। अंत में पारस्परिक धन्यवाद के साथ समारोह संपन्न हुआ।

श्रीश्याम बालाजी सेवादार मंडल ने बारस पर लगाया 40वां भंडारा

हिसार (राजधानी चौपाल)| श्रीश्याम बालाजी सेवादार मंडल की टीम ने आज बारस पर नई सब्जी मंडी में 40वां मासिक भंडारा लगाया। भंडारे की शुरुआत भाभड़ा बिरादरी के प्रधान गोबिंद बेदी और उनकी टीम के सदस्यों अनिल बेदी, सुरेंद्र डिगा, हरीश द्वारा पूजा-अर्चना व भोग लगवाकर की गई।

मंडल के सदस्यों ने आए हुए अतिथियों का पटका पहनाकर अभिनंदन किया। इस अवसर पर मंडल के प्रधान सुरेन्द्र बालान, कोषाध्यक्ष अरुण सेठी, वरिष्ठ सदस्य प्रवीण सहारण, सुरेंद्र बागड़ी, गजानंद, अतुल बागड़ी, कृष्ण सैनी, सुमित, सुभाष सैनी, राजू, हैप्पी सैनी, डॉक्टर मोहित, अशोक वर्मा, राजेंद्र सैनी, राकेश, हैप्पी बालान, बिट्टू तनेजा, संजय शर्मा, राकेश, बंसी, अमनदीप, डॉ. संजय, सौरभ, मामन राम सैनी, ललित सैनी, गुलशन गाबा, संजय मिथुन, संदीप जांगड़ा, यश सैनी, कुश कुकडेजा, रोबिन, विजय बालान, शम्मी बालान, तनु सैनी, अनिल बालान, लोकेश आदि उपस्थित रहे।

कौशिक नगर 3 दिवसीय सुरति योग शिविर सफलतापूर्वक सम्पन्न

हिसार (राजधानी चौपाल)| समर्थगुरु धारा, हिसार द्वारा समर्थगुरु धारा साधना केंद्र, कौशिक नगर में आयोजित तीन दिवसीय सुरति योग साधना शिविर अत्यंत श्रद्धा, अनुशासन और उत्साह के साथ सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। इस शिविर में शहर एवं आसपास के क्षेत्रों से अनेक साधकों ने भाग लिया और नियमित ध्यान, सत्संग एवं आध्यात्मिक मार्गदर्शन का लाभ प्राप्त किया। शिविर के दौरान साधकों को सुरति योग की गहन साधना पद्धति, एकाग्रता के विशेष अभ्यास तथा आंतरिक चेतना को जागृत करने की विधियों का प्रशिक्षण दिया गया। पूरे कार्यक्रम का वातावरण शांत, सकारात्मक एवं आध्यात्मिक ऊर्जा से ओत-प्रोत रहा। इस अवसर पर आचार्य सुभाष, आचार्य जितेंद्र, आचार्य गगन, मां साक्षी, आचार्य कृष्ण उत्सव एवं बसंत सहित सभी आचार्यों ने विभिन्न सत्रों में साधकों का मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम के सफल आयोजन में सभी सेवाधारियों एवं साधकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अंत में आयोजकों ने भविष्य में भी इस प्रकार के आध्यात्मिक शिविर नियमित रूप से आयोजित करने का संकल्प व्यक्त किया।

न्यूज ब्रीफ

समृद्ध भारत परिषद ने होली महोत्सव एवं परिवार मिलन समारोह मनाया

हिसार (राजधानी चौपाल)| समृद्ध भारत परिषद द्वारा दिल्ली रोड़ स्थित शीश महल में होली महोत्सव एवं परिवार मिलन समारोह का आयोजन किया गया। संस्था के प्रधान विकास लाहौरिया ने बताया कि होली मिलन कार्यक्रम मनाने से आपस में भाईचारा बढ़ता है। समाज में एकता और सुदृढ़ होती है तथा आपस में प्रेम-प्यार की भावना बनी रहती है। सचिव डॉक्टर अजीत कुमार ने बताया कि समारोह में 15 विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए गोद लिया गया। कार्यक्रम के दौरान अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर तिलक महता, संजीव शर्मा, विजय अग्रवाल, दीपक अग्रवाल, राजेश गुप्ता, तरुण बंसल सहित अनेक गणमान्य सदस्य उपस्थित रहे।

गुरुद्रोणाचार्य इंटरनेशनल स्कूल में सामाजिक विज्ञान प्रदर्शनी का भव्य आयोजन

मण्डी आदमपुर (राजधानी चौपाल)| मण्डी आदमपुर स्थित गुरुद्रोणाचार्य इंटरनेशनल स्कूल में सामाजिक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ किया गया। इस अवसर पर विद्यालय परिसर ज्ञान, जिज्ञासा और रचनात्मकता का केंद्र बन गया। विद्यार्थियों ने इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र एवं अर्थशास्त्र से जुड़े आकर्षक और ज्ञानवर्धक मॉडल प्रस्तुत कर अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। प्राचीन सभ्यताओं, भारतीय संविधान, प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण और मानचित्र आधारित परियोजनाओं ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। विद्यार्थियों की प्रस्तुति शैली, आत्मविश्वास और विषय की गहरी समझ ने अभिभावकों और आगंतुकों को प्रभावित किया। प्रदर्शनी के दौरान अभिभावकों ने बच्चों के मॉडलों का अवलोकन कर उनके प्रयासों की भरपूर सराहना की। शिक्षकों के कुशल मार्गदर्शन में विद्यार्थियों ने सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों को सरल, रोचक और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। यह प्रदर्शनी विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सीख का अवसर साबित हुई, जिसने उनमें सामाजिक जागरूकता, जिम्मेदारी और राष्ट्र के प्रति कर्तव्य भावना को सुदृढ़ किया।

गुरु द्रोणाचार्य गर्ल्स कॉलेज में होली की पूर्व संध्या पर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन

मण्डी आदमपुर (राजधानी चौपाल)| गुरु द्रोणाचार्य गर्ल्स कॉलेज में होली की पूर्व संध्या पर होली का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया गया। कॉलेज परिसर रंग-बिरंगी सजावट और उत्साह से सराबोर नजर आया। छात्राओं ने बोर्ड डेकोरेशन के माध्यम से अपनी रचनात्मक प्रतिभा का सुंदर प्रदर्शन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कॉलेज के निर्देशक अजय ज्याणी, प्राचार्या डॉ. अमिता ग्रेवाल एवं उप-प्राचार्या श्रीमती सुनीता रहेजा ने की। निर्देशक अजय ज्याणी ने अपने संबोधन में कहा कि होली का पर्व हमें आपसी प्रेम, भाईचारे और सौहार्द का संदेश देता है। उन्होंने छात्राओं को सकारात्मक सोच के साथ जीवन में आगे बढ़ने और भारतीय संस्कृति के मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। प्राचार्या डॉ. अमिता ग्रेवाल ने कहा कि होली केवल रंगों का ही नहीं, बल्कि मन के विकारों को दूर कर नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का त्योहार है। उन्होंने छात्राओं को अनुशासन और गरिमा के साथ त्योहार मनाने का संदेश दिया। उप-प्राचार्या श्रीमती सुनीता रहेजा ने अपने उद्बोधन में कहा कि इस प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम छात्राओं के व्यक्तित्व विकास में सहायक होते हैं।

कर्जे की बैसाखियों पर टिका हरियाणा का बजट, विकास के नाम पर केवल लफ्फाजी : हुड्डा

नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा में बजट की धज्जियां उड़ाईं; 5.56 लाख करोड़ के कुल कर्ज का दावा, बोले— सरकार नए कर्ज से पुराने लोन की भर रही है किस्तें

चंडीगढ़ (राजधानी चौपाल) | मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा वित्त मंत्री के रूप में पेश किए गए वर्ष 2026-27 के बजट को मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने सिरे से नकार दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बजट भाषण के तुरंत बाद एक विस्तृत प्रेस वार्ता और सदन में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इस बजट को 'कोरी भाषणबाजी' और 'लफ्फाजी का पुलिंदा' करार दिया। हुड्डा ने आंकड़ों के जाल को सुलझाते हुए दावा किया कि हरियाणा की आर्थिक सेहत आईसीयू में है और सरकार केवल इवेंट मैनेजमेंट के जरिए जनता को गुमराह कर रही है।

कर्ज का चक्रव्यूह और 5.56 लाख करोड़ की भारी देनदारी

भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार के वित्तीय प्रबंधन पर सबसे बड़ा हमला 'कर्ज' को लेकर किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने हरियाणा को कर्ज के उस दलदल में धकेल दिया है, जिससे बाहर निकलना अब नामुमकिन सा लग रहा है। हुड्डा ने विस्तृत आंकड़े पेश करते हुए बताया कि राज्य पर कुल ऋण का बोझ अब 5,56,623 करोड़ तक पहुंच चुका है। इसमें आंतरिक ऋण, छोटी बचतें, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का कर्ज और बिजली सब्सिडी की बकाया देनदारियां शामिल हैं। हुड्डा ने तंज कसते हुए कहा कि सरकार इस साल जो नया आंतरिक ऋण उठाने जा रही है, उसका बड़ा हिस्सा केवल पुराने कर्ज का मूलधन और ब्याज चुकाने में ही निकल जाएगा। उनके अनुसार, जब कर्ज लेकर केवल पुराना कर्ज ही चुकाया जा रहा है, तो नए विकास कार्यों के लिए वास्तविक निवेश संभव ही नहीं है।

शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी क्षेत्रों की उपेक्षा

नेता प्रतिपक्ष ने सामाजिक बुनियादी ढांचे की अनदेखी पर सरकार को घेरते हुए कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को बजट में दरकिनार कर दिया गया है। शिक्षा के लिए आवंटित बजट कुल खर्च का मात्र 6.2 प्रतिशत है, जो नई शिक्षा नीति की सिफारिशों के मुकाबले बहुत कम है। इसी प्रकार, स्वास्थ्य क्षेत्र को दिया गया बजट भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के मानकों पर खरा नहीं उतरता। हुड्डा ने आंकड़ों के हवाले से बताया कि जीडीपी के अनुपात में ये आवंटन इतने कम हैं कि प्रदेश के स्वास्थ्य और शैक्षिक स्तर में सुधार की कल्पना करना भी बेमानी है।

लाडो लक्ष्मी योजना में आंकड़ों की बाजीगरी का आरोप

बजट की सबसे चर्चित घोषणा 'लाडो लक्ष्मी योजना' को लेकर हुड्डा ने सरकार की नीयत पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने इसे मात्र एक 'चुनावी खेल' बताते हुए कहा कि सरकार ने बजट में इसके लिए पर्याप्त फंड का प्रावधान ही नहीं किया है। हुड्डा का तर्क है कि हरियाणा में 18 से 60 वर्ष की आयु की लगभग 82.5 लाख महिलाएं हैं और यदि वादे के मुताबिक प्रत्येक महिला को 2,100 प्रति माह दिए जाएं, तो सालाना 20,790 करोड़ की आवश्यकता होगी। हालांकि, बजट में इसके लिए मात्र 6,500 करोड़ रखे गए हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि लगभग 67 प्रतिशत महिलाएं इस लाभ से वंचित रह जाएंगी।

कृषि प्रधान प्रदेश में किसानों की अनदेखी और विकास की सुस्त चाल

कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर बोलते हुए हुड्डा ने कहा कि हरियाणा की 70 प्रतिशत आबादी खेती पर निर्भर है, लेकिन सरकार ने बजट का एक बहुत छोटा हिस्सा ही इस क्षेत्र को दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बजट में न तो किसानों की आय दोगुनी करने का कोई खाका है और न ही एमएसपी की कानूनी गारंटी के लिए कोई फंड।

हुड्डा ने प्रति व्यक्ति आय की तुलना करते हुए कहा कि कांग्रेस शासन में आय बढ़ने की रफ्तार भाजपा के मुकाबले दोगुनी से भी अधिक थी। उनके अनुसार, भाजपा के 10 वर्षों में आय की वृद्धि दर इतनी धीमी रही है कि हरियाणा आर्थिक रूप से पिछड़ता जा रहा है।

बेरोजगारी, उद्योगों का पलायन और जल संकट पर चुप्पी

रोजगार के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हरियाणा आज बेरोजगारी में देश में अव्वल स्थान पर है। भाजपा की गलत नीतियों के कारण राज्य में नया निवेश नहीं आ रहा है और पहले से स्थापित उद्योग भी अन्य राज्यों की ओर पलायन कर रहे हैं। हुड्डा ने पर्यावरण और जल संकट के मुद्दे पर भी सरकार को आड़े हाथों लिया।

उन्होंने कहा कि 11 साल सत्ता में रहने के बाद सरकार को अब यमुना की सफाई याद आई है, जबकि प्रदूषित हवा और पानी के मामले में हरियाणा की स्थिति बदतर हो चुकी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि मुख्यमंत्री ने खेती के लिए पानी की कमी तो मानी, लेकिन पंजाब से हरियाणा के हिस्से का एसवाईएल (SYL) का पानी लाने के लिए कोई ठोस योजना पेश नहीं की।

तबादलों से बढ़ा असंतुलन... जेबीटी-पीआरटी अंतर जिला ट्रांसफर ड्राइव का परिणाम जारी

करनाल से सबसे ज्यादा 488 शिक्षक ट्रांसफर किए, पोस्टिंग के लिए गुरुग्राम बना पहली पसंद

चंडीगढ़ (राजधानी चौपाल) | प्रदेश में जूनियर बेसिक ट्रेनिंग (जेबीटी) और प्राथमिक शिक्षक (पीआरटी) की अंतर जिला ट्रांसफर ड्राइव का परिणाम जारी होते ही शिक्षा व्यवस्था की नई तस्वीर सामने आई है। आंकड़े बताते हैं कि जिन जिलों में पहले से शिक्षकों की कमी थी, वहीं सबसे ज्यादा असर पड़ा है। ट्रांसफर ड्राइव के बाद सबसे ज्यादा फरीदाबाद, सिरसा और पलवल जैसे जिले प्रभावित रहे। जहां पहले से ही शिक्षकों की भारी कमी थी।

बता दें कि फरीदाबाद में पहले से ही 108 पद रिक्त थे। ड्राइव के दौरान 400 टीचर के और तबादले हो गए, लेकिन मिले महज 42 हैं। ऐसे में खाली पोस्ट बढ़कर 466 हो गई हैं। इसी प्रकार पलवल में 405 पद रिक्त थे। 198 टीचर चले गए और आए महज 58 टीचर। यहां भी खाली पद बढ़कर 545 हो गए हैं। सिरसा में 212 रिक्त पद रिक्त थे। 117 और चले गए, लेकिन आए केवल 58 हैं। खाली पद बढ़कर 271 हो गए हैं। गुरुवार शाम को अंतर जिला परिणाम जारी होने के बाद बताया जा रहा है कि मार्च के दूसरे सप्ताह तक स्टेशन भी अलॉट कर दिए जाएंगे। वहीं, शेड्यूल के अनुसार सभी की ज्वॉइनिंग और रिलीविंग 1 अप्रैल को ही होगी। ऐसे में जहां से शिक्षकों की कमी थी वहीं और परेशानी बढ़ गई है।

राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के राज्य प्रवक्ता अमित छाबड़ा ने कहा कि टीचर्स के हित को देखते हुए विभाग की ओर से ट्रांसफर ड्राइव तो चला दी गई है। टीचर्स को उनका गृह जिला भी मिल गया, जिन जिलों में पहले से ही टीचर्स की भारी कमी

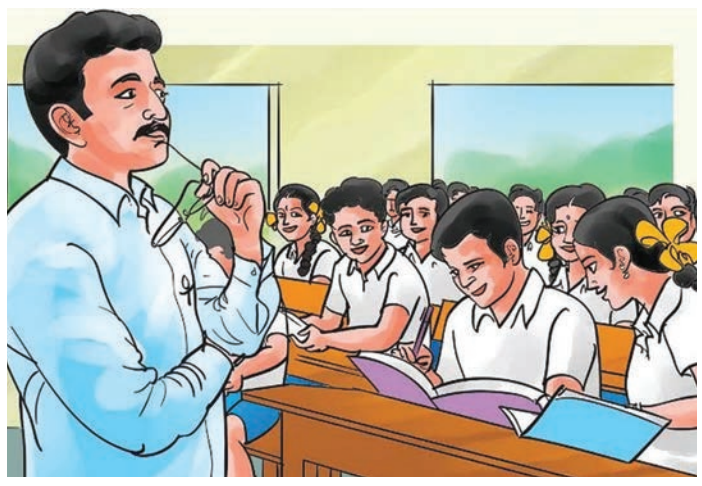

थी, वहां ड्राइव के बाद छात्र और शिक्षक का अनुपात और ज्यादा बिगड़ गया है। ऐसे में जहां टीचर्स की भारी कमी है, वहां स्थायी भर्ती से संतुलन जरूरी है, ताकि 1 अप्रैल से छात्रों संख्या में गिरावट की आशंका न बने।

शहरी व एनसीआर से सटे जिले पहली पसंद : ट्रांसफर ड्राइव के तहत शहरी और एनसीआर से सटे जिले टीचर्स की पहली पसंद रहे। गुरुग्राम 613 टीचरों की पसंद बना, जबकि पानीपत में 293 और सोनीपत में 279 टीचर पहुंचे। वहीं, करनाल से 488 और फरीदाबाद से 400 टीचर अन्य जिलों में चले गए, जिससे इन जिलों में सबसे ज्यादा नेट लॉस दर्ज हुआ। महेंद्रगढ़ से केवल एक टीचर का तबादला हुआ और वहां बाहर से कोई नहीं आया।

990 टीचर्स को प्राथमिकता के आधार पर मिला जिला : ट्रांसफर ड्राइव के तहत 2080 टीचर्स ने अपनी प्राथमिकताएं दर्ज कराई। इसमें से 990 टीचर्स को तो उनकी पहली प्राथमिकता के आधार पर ही उनका गृहजिला अलॉट कर दिया गया। जबकि 515 को दूसरे, 231 को तीसरे व 104 टीचर्स को चौथे नंबर पर दर्ज प्राथमिकता के आधार पर गृहजिला या उसके आसपास का जिला अलॉट किया गया।

कहां सबसे ज्यादा आए और कहां से सबसे ज्यादा गए : सबसे ज्यादा गुरुग्राम में 613, पानीपत में 293, सोनीपत में 279, फतेहाबाद में 210 व पंचकूला में 103 टीचर आए हैं। जबकि करनाल से 488, फरीदाबाद से 400, पलवल से 198, पानीपत से 154 तो कुरुक्षेत्र से 128 टीचर चले गए हैं। जबकि रेवाड़ी, मेवात (नूंह), चरखी दादरी और महेंद्रगढ़ से कोई टीचर ट्रांसफर नहीं हुआ।

किस जिले की स्थिति बिगड़ी

जिला	पहले कमी	गए	आए	अब कमी
यमुनानगर	743	108	20	831
पलवल	405	198	58	545
फरीदाबाद	108	400	42	466
अम्बाला	450	71	39	482
सिरसा	212	117	58	271
भिवानी	100	26	5	121

कितने गए और आए शिक्षक

जिला	गए	आए	नेट
करनाल	488	36	-452
फरीदाबाद	400	42	-358
पलवल	198	58	-140
पानीपत	154	293	+139
कुरुक्षेत्र	128	30	-98
सिरसा	117	58	-59
यमुनानगर	108	20	-88
अम्बाला	71	33	-38
कैथल	59	73	+14
सोनीपत	59	279	+220
गुरुग्राम	57	613	+556
फतेहाबाद	52	210	+158
जींद	40	8	-32
पंचकूला	31	103	+72
भिवानी	26	4	-22
रेवाड़ी	22	0	-22
झज्जर	20	50	+30
रोहतक	15	99	+84
नूंह	13	0	-13
हिसार	11	71	+60
चरखी दादरी	10	0	-10
महेंद्रगढ़	1	0	-1

विधानसभा में महकी फूलों की खुशबू: मुख्यमंत्री ने सहयोगियों संग खेली होली

चंडीगढ़ (राजधानी चौपाल) | हरियाणा विधानसभा में सोमवार का दिन केवल नीतिगत चर्चाओं और बजट के आंकड़ों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि यहाँ राजनीति की कड़वाहट को भुलाकर आपसी सौहार्द के खूबसूरत रंग देखने को मिले। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा सदन में वर्ष 2026-27 का बजट भाषण प्रस्तुत करने के ठीक बाद, विधानसभा परिसर पारंपरिक हर्षोल्लास और फूलों की खुशबू से सराबोर हो गया।

विधानसभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण की अगुवाई में मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद के सदस्य, पक्ष-विपक्ष के विधायक और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी सदन के सेरेमोनियल गेट पर एकत्रित हुए। यहाँ 'फूलों की होली' का विशेष आयोजन किया गया, जहाँ मुख्यमंत्री ने सभी जनप्रतिनिधियों और पत्रकारों पर पुष्पवर्षा कर होली की शुभकामनाएं दीं। इस दौरान सदन की गंभीर बहस के बीच एक मुस्कुराहट भरा माहौल देखने को मिला, जहाँ सभी ने एक-दूसरे को गुलाल लगाकर सद्भावना का संदेश दिया। इस अवसर को और भी जीवंत बनाने के लिए कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग द्वारा रंगारंग प्रस्तुतियां दी गईं। हरियाणा की समृद्ध लोक संस्कृति को दर्शाते फाग गीतों और ढोल की थाप ने पूरे परिसर को उत्सव के माहौल में बदल दिया। कलाकारों के नृत्य ने मुख्यमंत्री और वहां मौजूद सभी लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि त्योहार हमारी संस्कृति की धरोहर हैं, जो आपसी मतभेदों को भुलाकर भाईचारे और एकता को मजबूत करते हैं। विधानसभा परिसर में खेली गई यह फूलों की होली लोकतंत्र की उस गरिमा का प्रतीक बनी, जहाँ वैचारिक मतभेदों के बावजूद मानवीय रिश्ते सर्वोपरि रहते हैं।

दुष्यंत ने नाम लिए बिना मंत्री कृष्ण बेदी पर पलटवार किया

'गैबी साहब' के तालाब का काम किसी मंत्री ने नहीं, आप लोगों ने कराया: दुष्यंत

नरवाना (जींद) (राजधानी चौपाल)| पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पार्टी का संगठन घोषित हो चुका है। आज की परिस्थितियों में जनता को जागरुक करने का कार्य करें। उन्होंने कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी का नाम लिए बिना कहा कि एक नेता जो अब मंत्री हैं, कहते हैं 'गैबी साहब' के तालाब का कार्य उनके द्वारा करवाया गया। जबकि वह कार्य आप सब लोगों की सहायता से हुआ था। यह बात उन्होंने रविवार को पब्लिक धर्मशाला में कार्यकर्ताओं की बैठक के दौरान कही। दुष्यंत 13 मार्च को डॉ. अजय सिंह चौटाला के जन्मदिन पर यहां होने वाली रैली के लिए न्योता देने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने वर्कर्स की ड्यूटियां भी लगाईं।

दुष्यंत ने कहा कि जब विधानसभा चुनाव में चंद्रशेखर को लेकर डॉ. अंबेडकर लाइब्रेरी में गए। अब उस लाइब्रेरी का बोर्ड हटाकर उसका नाम बदलकर अटल का नाम लिखवा दिया। यह जो लोग हैं, वह अब काम तो कर नहीं रहे, लेकिन आपके करवाए हुए कार्यों पर इश्तिहार जरूर लगा रहे हैं। उचाना में सीएम आए, हलके को लालीपॉप देकर चले गए। साल 2029 में भाजपा का झंड़ा फाड़ने की बात कहना आसान है। अब जजपा के हरेक कार्यकर्ता को आने वाले चार साल में पसीना निकालना बहुत जरूरी है। जनता के बीच में जाकर बताना होगा तभी 2029 में इनका झंडा फाड़ पाओगे। दुष्यंत ने कहा कि मैंने तो खुद इनमें रहकर काम किया है, यह बहुत शातिर लोग हैं। इनके मंत्री खुद कहते हैं कि आप तो 4 वर्ष राज कर गए, हमारे पल्ले कुछ नहीं है।

पूर्व विधायक भाटिया ने प्रॉपर्टी फ्रॉड के आरोपों को निराधार बताया

फरीदाबाद (राजधानी चौपाल)| पूर्व विधायक चंद्र भाटिया ने अपने ऊपर लगे प्रॉपर्टी फ्रॉड के आरोप को निराधार बताया। उन्होंने कहा दो-तीन दिन से यह प्रचार किया जा रहा है कि उन्होंने 70 से 80 लाख रुपए लेकर एक प्लॉट की रजिस्ट्री में गड़बड़ी करा किसी अन्य व्यक्ति के नाम संपत्ति ट्रांसफर करा दी। भाटिया ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहाकि उनका इस विवादित प्लॉट से कोई लेना-देना नहीं है। उन्हें इस संपत्ति के बारे में पहले कोई जानकारी भी नहीं थी। उन्होंने कहा वह दो बार विधायक रह चुके हैं। उनके पिता भी विधायक रहे हैं। इतने लंबे सार्वजनिक जीवन में कभी उनके परिवार पर इस तरह का आरोप नहीं लगा।

अब जींद में 23 को इनेलो का युवा सम्मेलन: करण

चंडीगढ़ (राजधानी चौपाल)| इनेलो युवा सम्मेलन का बदला स्थानः अब 23 मार्च को जींद की नई अनाज मंडी में भरेंगे हुंकार नरवाना के बजाय जींद को चुनने के पीछे कार्यकर्ताओं की मांग और बड़ी क्षमता; करण चौटाला बोले— रोजगार की अनदेखी पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेगा युवा चंडीगढ़ (राजधानी चौपाल ब्यूरो): इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) के युवा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय प्रभारी करण चौटाला ने रविवार को पार्टी की आगामी रणनीति को लेकर एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। उन्होंने बताया कि आगामी 23 मार्च को आयोजित होने वाले प्रदेश स्तरीय 'युवा सम्मेलन' के स्थान में परिवर्तन किया गया है। अब यह सम्मेलन नरवाना के स्थान पर जींद की नई अनाज मंडी में आयोजित किया जाएगा।

कनेक्टिविटी और विशाल क्षमता करण चौटाला ने स्पष्ट किया कि प्रदेश के सभी जिलों से कार्यकर्ताओं और युवा नेताओं की मांग आ रही थी कि कार्यक्रम स्थल को बदला जाए। सर्वसम्मति से लिए गए इस निर्णय के पीछे जींद की नई अनाज मंडी की विशाल क्षमता एक बड़ा कारण है। नरवाना की तुलना में यहाँ कई गुना अधिक युवाओं के बैठने की व्यवस्था है। साथ ही, जींद हरियाणा के मध्य में होने के कारण सभी जिलों से आने वाले युवाओं के लिए परिवहन और पहुंचने के लिहाज से बेहद सुलभ है।

2026 में बिजली कटौती की शिकायतों के समाधान का समय बढ़ा

बिजली आपूर्ति में गुरुग्राम - नंबर 1 व हिसार, जींद के गांवों में रोजाना औसत 19 घंटे सप्लाई हो रही

गुरुग्राम (राजधानी चौपाल) | बिजली निगम द्वारा प्रदेश में 23 से 24 घंटे बिजली आपूर्ति का दावा किया जाता है। अप्रैल-2025 से फरवरी-2026 तक आंकड़े बताते हैं कि शहरी क्षेत्रों - को 23:30 से 23:55 घंटे तक बिजली मिल रही है। - जब शहरों की गांवों से तुलना करते हैं तो शहरों में 23 - से 24 घंटे सप्लाई है, वहीं कई गांवों में आपूर्ति 18 से - 21 घंटे के बीच सीमित है। हिसार, फतेहाबाद, जींद - के ग्रामीण क्षेत्रों में सप्लाई महज 19 घंटे के आसपास सीमित है। बेहतर प्रदर्शन के मामले में गुरुग्राम - नंबर - 1, रेवाड़ी व पंचकूला मॉडल सबसे संतुलित हैं। यहां - ग्रामीण व शहरी सप्लाई लगभग बराबर है। पड़ताल में सामने आया कि 2025 की अपेक्षा - 2026 में बिजली कटौती की शिकायतों के निस्तारण का समय बढ़ गया है। 2019 में शिकायत समाधान बहुत धीमा था, 2020-22 में सुधार हुआ। अब 2023-2026 में फिर समय बढ़ा है। 2025 में जहां बिजली कटौती को लेकर यूएचबीवीएन व - डीएचबीवीएन दोनों निगमों को करीब 37.42 लाख - शिकायतें मिलीं, शिकायतों के निपटान का औसत समय 1:49 घंटे रहा। 2026 में 2.58 लाख - शिकायतें आईं, निपटान का समय बढ़कर 3:32 - घंटे तक पहुंच गया है। 2026 यूएचबीवीएन को 1.36 लाख शिकायतें मिलीं, निपटान का औसत समय 3:32 घंटे रहा, वहीं डीएचबीवीएन को 1.21 शिकायतें मिलीं, निस्तारण का समय 2:49 घंटे रहा।

बेहतर प्रदर्शन वाले क्षेत्र : गुरुग्राम-1 में शहरी सप्लाई 23:37 घंटे, ग्रामीण आपूर्ति 23:21 घंटे रही। रेवाड़ी में शहरी 23:31 घंटे, ग्रामीण आपूर्ति 23:18 घंटे है। गुरुग्राम-2 में शहरी आपूर्ति 23:50 घंटे, ग्रामीण आपूर्ति 22:52 घंटे है। पंचकूला में शहरी आपूर्ति 23:47 घंटे तो ग्रामीण आपूर्ति 23:03 घंटे का है।

हिसार में शहरी आपूर्ति 23:54 घंटे, ग्रामीण 19:21 घंटे तक सिमटी : हिसार में शहरी क्षेत्रों में 23:54 घंटे की आपूर्ति मिल रही है, वहीं यह अंतर घटकर ग्रामीणों क्षेत्रों में 19:21 घंटे तक सिमट रहा है। यानी अंतर 4:33 घंटे का है। फतेहाबाद में शहरी आपूर्ति 23:21 घंटे है, ग्रामीण आपूर्ति 19:09 घंटे है। जींद में शहरी आपूर्ति 23:30 घंटे है, जबकि ग्रामीण आपूर्ति घटकर 19:16 घंटे तक सिमट रही है।

यमुनानगर, कुरुक्षेत्र में शिकायतों के समाधान का समय बढ़ा : 2025 में यमुनानगर में शिकायतों के निस्तारण का समय 1:17 घंटे था, 2026 में बढ़कर 5:54 घंटे हो गया। कुरुक्षेत्र में 2025 में जहां 1:01 घंटे का समय लगता था, 2026 में समय बढ़कर 4:29 घंटे का हो गया है।

राजधानी चौपाल

समाचार पत्र में किसी भी प्रकार के समाचार, विज्ञप्ति और विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें...

94169-26329
93068-13001

संपादकीय...

नशे की भेंट चढ़ती होली की गरिमा और सुरक्षा

होली भारतीय जनमानस के उल्लास, आपसी सौहार्द और बुराई पर अच्छाई की विजय का पर्व है। फागुन की बयार और रंगों की बौछार मन की कड़वाहट मिटाने के लिए होती है, न कि उसे नशे के उन्माद में डुबाने के लिए। लेकिन दुर्भाग्यवश, आधुनिक समय में होली की परिभाषा 'हुड़दंग और नशे' तक सिमटती जा रही है। विशेषकर युवाओं में नशे को "त्योहार की मस्ती" का अनिवार्य हिस्सा मानने की प्रवृत्ति एक गंभीर सामाजिक और सुरक्षा संकट बन गई है।

होली के दिन शराब और भांग जैसे नशीले पदार्थों का सेवन न केवल व्यक्ति के विवेक को मार देता है, बल्कि यह सड़क हादसों का सबसे बड़ा कारण भी बनता है। जब 'बुरा न मानो होली है' का नारा लगाकर कोई नशेड़ी स्टेयरिंग या हैंडल थामता है, तो वह सड़क पर चलते मासूमों के लिए यमदूत बन जाता है। यह चिंताजनक है कि उत्सव की आड़ में हम आत्म-नियंत्रण खो देते हैं, जिससे खुशियों का रंग लहू के लाल रंग में बदल जाता है। नशा हमारी निर्णय लेने की क्षमता को शून्य कर देता है, जिसका परिणाम अक्सर सड़क पर बिखरे मलबे और टूटी जिंदगियों के रूप में सामने आता है।

इसके अलावा, नशा मर्यादाओं की रेखा को भी धुंधला कर देता है। होली के हुड़दंग में महिलाओं के साथ अभद्रता और आपसी मारपीट की अधिकांश घटनाएं नशे की ही उपज होती हैं। हम भूल जाते हैं कि जिस त्योहार का मूल संदेश 'प्रेम' है, वहां 'जबरदस्ती और अभद्रता' के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। संस्कृति को विकृति से बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। यदि हम उत्सव के नाम पर अराजकता को मौन स्वीकृति देते हैं, तो हम अपनी आने वाली पीढ़ी को एक असुरक्षित और संस्कारविहीन समाज विरासत में देंगे।

आज समय की मांग है कि हम इस पर्व को उसके सात्विक स्वरूप में वापस लाएं। प्रशासन अपनी ओर से मुस्तैद रहता है, लेकिन संस्कार पुलिस के डंडे से नहीं, समाज की चेतना से आते हैं। अभिभावकों को चाहिए कि वे स्वयं संयम का उदाहरण बनें और युवाओं को यह समझाएं कि उत्सव का आनंद 'होश' में रहने में है, 'बेहोशी' में नहीं। आइए, इस वर्ष संकल्प लें कि हमारी होली नशामुक्त होगी। खुशियों के रंगों में नशे की कालिख न मिलने दें। याद रखें, घर पर कोई आपका इंतज़ार कर रहा है; सुरक्षित रहें और अपनों को भी सुरक्षित रखें।

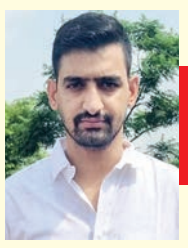

राहुल हिंदुस्तानी
संपादक
राजधानी चौपाल

रंगों में संस्कार, उत्सव में उत्तरदायित्व

परंपरागत होली और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प

पर्यावरण-मित्र होली: व्यवहारिक सुझाव

- **प्राकृतिक रंग अपनाएँ** – घर पर फूलों, चुकंदर, हल्दी और बेसन से रंग बनाए जा सकते हैं।
- **सूखी होली खेलें** – गुलाल से भी उत्सव उतना ही आनंददायक होता है।
- **सामूहिक होलिका दहन** – हर गली में अलग-अलग अलाव के बजाय एक सामूहिक आयोजन से लकड़ी की बचत होगी।
- **पेड़ों की कटाई रोकें** – सूखी लकड़ियों का उपयोग करें।
- **पानी की सीमा तय करें** – बच्चों को समझाएँ कि पानी अनमोल है।
- **पशुओं का ध्यान रखें** – जानवरों पर रंग न डालें।
- **स्वच्छता का संकल्प लें** – होली के बाद सड़कों और मोहल्लों की सफाई सुनिश्चित करें।

रंगों से अधिक रिश्तों का पर्व

भारत की संस्कृति उत्सवधर्मिता से भरी हुई है। हर ऋतु, हर परिवर्तन और हर सामाजिक अवसर को हमने त्योहारों के रूप में जिया है। इन्हीं पर्वों में होली का स्थान अत्यंत विशिष्ट है। यह केवल रंगों का उत्सव नहीं, बल्कि मन के द्वेष को धोने और समाज को जोड़ने का अवसर है।

होली हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठोरता क्यों न हो, प्रेम और भाईचारे के रंग सब कुछ सहज बना सकते हैं। यह पर्व सामाजिक समरसता, सौहार्द और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। लेकिन आज आवश्यकता है कि हम होली के उत्साह के साथ उसके उत्तरदायित्व को भी समझें। क्या हमारी होली प्रकृति के अनुकूल है? क्या हम आने वाली पीढ़ियों के हिस्से का पानी आज ही बहा नहीं रहे? इन्हीं प्रश्नों के साथ यह संपादकीय लेख पाठकों के सामने है—परंपरागत होली की ओर लौटने और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेने का आह्वान करता हुआ।

पौराणिक पृष्ठभूमि : आस्था की अग्नि

होली का मूल आधार भक्त प्रह्लाद और होलिका की कथा से जुड़ा है। यह केवल एक धार्मिक कथा नहीं, बल्कि नैतिकता का संदेश है—अहंकार का अंत और सत्य की विजय। होलिका दहन केवल लकड़ियों का दहन नहीं, बल्कि हमारे भीतर के नकारात्मक विचारों का दहन है। यह हमें आत्मचिंतन का अवसर देता है—क्या हमने अपने भीतर की ईर्ष्या, द्वेष और कटुता को जलाया? यदि होली के मूल संदेश को समझ लिया जाए, तो यह पर्व स्वयं ही संयम और मर्यादा की सीख दे देता है।

ऋतु परिवर्तन और वैज्ञानिक दृष्टि

होली वसंत ऋतु में आती है। यह वह समय है जब सर्दी विदा लेती है और गर्मी का आगमन होता है। पुराने समय में प्राकृतिक रंगों से खेलना और होलिका दहन करना वातावरण को शुद्ध करने का माध्यम माना जाता था। टेसू (पलाश) के फूलों से बने रंग त्वचा के लिए लाभकारी होते थे। हल्दी और चंदन रोगाणुरोधी गुण रखते थे। इस प्रकार होली केवल उत्सव नहीं, स्वास्थ्य और प्रकृति का संतुलन भी थी। आज विज्ञान भी यह मानता है कि प्राकृतिक तत्वों का उपयोग पर्यावरण और शरीर दोनों के लिए हितकारी है।

पारंपरिक होली: सादगी और संवेदना

ग्रामीण भारत में होली की छवि आज भी कहीं-कहीं जीवित है—ढोलक की थाप, फाग के गीत, सीमित रंग और ढेर सारा अपनापन। पहले लोग सुबह घर-घर जाकर गुलाल लगाते थे। पानी का प्रयोग बहुत कम होता था। होली मिलन का अर्थ था गले लगना, मिठाई बांटना और मन की गांठें खोल देना। आज आवश्यकता है कि हम उसी सरल और सच्ची होली की ओर लौटें।

रासायनिक रंग: एक छुपा हुआ खतरा

बाजार में बिकने वाले सस्ते रंगों में कई बार हानिकारक रसायन मिलाए जाते हैं। इनमें सीसा, क्रोमियम, कॉपर सल्फेट और कृत्रिम डाई शामिल हो सकते हैं। इनसे त्वचा रोग, एलर्जी, आंखों में जलन और बालों को नुकसान हो सकता है। इतना ही नहीं, ये रंग नालियों के माध्यम से जलस्रोतों में पहुँचकर प्रदूषण बढ़ाते हैं। प्रकृति को हानि पहुँचाकर मनाया गया उत्सव क्या सच में उत्सव कहलाएगा?

जल संकट: एक गंभीर सच्चाई

भारत के अनेक क्षेत्रों में जल स्तर तेजी से गिर रहा है। गर्मियों के आते-आते कई गाँव और शहर पानी के संकट से जूझने लगते हैं। ऐसे में होली पर हजारों लीटर पानी का उपयोग केवल मनोरंजन के लिए करना क्या उचित है? सूखी होली केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि समय की आवश्यकता है। जल संरक्षण आज राष्ट्रधर्म बन चुका है।

सामाजिक मर्यादा और होली

दुर्भाग्यवश कुछ स्थानों पर होली के नाम पर हुड़दंग, अश्लीलता और नशाखोरी देखी जाती है। यह हमारी संस्कृति के अनुरूप नहीं है। होली मर्यादा का पर्व है। यह महिलाओं के सम्मान और समाज की गरिमा को बनाए रखते हुए मनाया जाना चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि उत्सव आनंद का हो, अराजकता का नहीं।

प्रशासन और समाज की साझी जिम्मेदारी

प्रशासन को चाहिए कि अवैध और हानिकारक रंगों की बिक्री पर नियंत्रण रखे। जल संरक्षण के प्रति जागरूकता अभियान चलाए जाएँ। विद्यालयों, सामाजिक संगठनों और मीडिया को आगे आकर पर्यावरण-मित्र होली का संदेश देना चाहिए। यदि समाज और शासन साथ मिलकर कार्य करें, तो बदलाव संभव है।

युवा शक्ति: परिवर्तन का आधार

आज का युवा वर्ग जागरूक है। सोशल मीडिया के माध्यम से संदेश तेजी से फैलता है। यदि युवा "ग्रीन होली" का अभियान चलाएँ, प्राकृतिक रंगों को बढ़ावा दें और जल संरक्षण का संदेश दें, तो समाज पर उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। परिवर्तन की शुरुआत युवाओं से ही होती है।

आर्थिक पहलू: स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा

प्राकृतिक रंगों का उपयोग स्थानीय कारीगरों और छोटे उद्योगों को भी प्रोत्साहित कर सकता है। यदि हम स्वदेशी और प्राकृतिक उत्पादों को अपनाएँ, तो यह स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए भी लाभकारी होगा। इस प्रकार पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक सशक्तिकरण दोनों साथ-साथ चल सकते हैं।

मीडिया की भूमिका

मीडिया समाज का दर्पण है। अखबार, टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म यदि जिम्मेदार होली का संदेश दें, तो जनमानस पर गहरा प्रभाव पड़ता है। "राजधानी चौपाल" जैसे मंच का दायित्व है कि वह जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से उठाए और समाज को सकारात्मक दिशा दे।

संकल्प की होली

आइए इस वर्ष होली को केवल रंगों का उत्सव न रहने दें, बल्कि इसे संकल्प का पर्व बनाएं।

- हम रासायनिक रंगों का बहिष्कार करेंगे।
- हम पानी की बर्बादी नहीं करेंगे।
- हम पेड़ों की रक्षा करेंगे।
- हम सामाजिक मर्यादा बनाए रखेंगे।

भविष्य के लिए जिम्मेदार बनें

होली हमें जोड़ती है। यह पर्व हमें सिखाता है कि जीवन रंगों से भरा होना चाहिए, पर संतुलन के साथ। प्रकृति हमारी धरोहर है। जल हमारा जीवन है। यदि हमने आज सावधानी नहीं बरती, तो आने वाली पीढ़ियाँ हमें क्षमा नहीं करेंगी। इस बार होली का अर्थ केवल "बुरा न मानो होली है" न होकर "बुरा न करो, प्रकृति है" होना चाहिए।

आइए मिलकर ऐसी होली मनाएँ
जहाँ रंग हों, पर प्रदूषण न हो।
जहाँ उत्सव हो, पर अपव्यय न हो।
जहाँ आनंद हो, पर जिम्मेदारी भी हो।
यही सच्ची होली है।
यही हमारी संस्कृति है।
यही हमारा भविष्य है।

-राहुल हिंदुस्तानी
संपादक, राजधानी चौपाल

सड़क सुरक्षा - एक साझा जिम्मेदारी, एक अनमोल जीवन...

सड़क केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का माध्यम या डामर की बिछी हुई कोई निर्जीव पट्टी नहीं है; यह हमारे जीवन की धड़कन और राष्ट्र की प्रगति की जीवन रेखा है। आधुनिक युग में गति का विशेष महत्व है, और इसी गति को बनाए रखने के लिए हम सड़कों का उपयोग करते हैं। हर सुबह जब करोड़ों लोग अपने घरों से दफ्तर, स्कूल या व्यापार के लिए निकलते हैं, तो उनके मन में एक ही आशा होती है—शाम को अपनों के बीच सकुशल वापसी।

परंतु, आज के दौर में सड़क पर निकलना एक अनचाहे जोखिम जैसा हो गया है। सड़कों पर बढ़ती भीड़ और आधुनिक वाहनों की तेज़ रफ़्तार के बीच 'सुरक्षा' कहीं पीछे छूट गई है। सड़क दुर्घटनाएं आज हमारे समाज के लिए किसी अदृश्य युद्ध से कम नहीं हैं, जहाँ हर दिन सैकड़ों लोग बिना किसी कारण के अपनी जान गंवा देते हैं। यह लेख केवल नियमों की जानकारी नहीं, बल्कि हमारे व्यवहार और मानसिकता में बदलाव का एक आह्वान है।

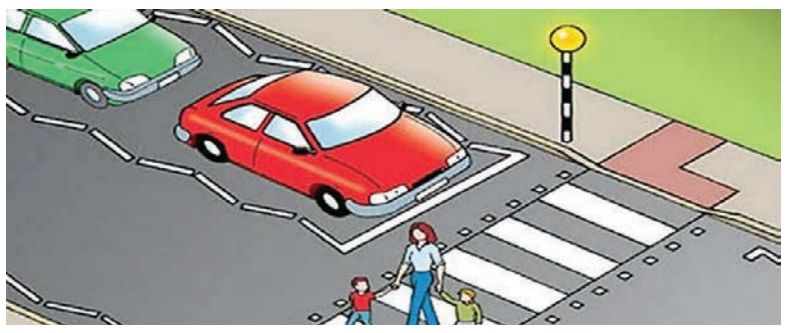

भयावह आंकड़े: मौतों का वह तांडव जिसे हम अनदेखा कर देते हैं

आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते, लेकिन वे बेहद कड़वे होते हैं। 'सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय' की वार्षिक रिपोर्टों के अनुसार, भारत दुनिया के उन देशों में अग्रणी है जहाँ सड़क हादसों में सबसे अधिक मृत्यु होती है।

- **एक राष्ट्रीय क्षति:** भारत में हर साल लगभग 1.5 लाख से अधिक लोग सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवाते हैं। इसका अर्थ है कि हर घंटे लगभग 18 से 20 लोग सड़क पर दम तोड़ देते हैं।
- **आर्थिक और सामाजिक आघात:** इन आंकड़ों के पीछे सिर्फ संख्या नहीं होती। जब परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य किसी हादसे का शिकार होता है, तो पूरा परिवार गरीबी और अंधकार के दलदल में धंस जाता है। कई बच्चे अनाथ हो जाते हैं और कई माता-पिता अपने बुढ़ापे का सहारा खो देते हैं। यह एक ऐसी सामाजिक क्षति है जिसकी भरपाई कोई भी सरकार या मुआवजा नहीं कर सकता।

क्यों लहूलुहान हो रही हैं सड़कें?

सड़क हादसों को अक्सर 'दुर्भाग्य' या 'ईश्वर की इच्छा' मानकर स्वीकार कर लिया जाता है, जबकि हकीकत में 90% हादसे मानवीय भूलों का परिणाम होते हैं।

- **तेज़ रफ्तार और जानलेवा ओवरटेकिंग :** 'गति रोमांच तो देती है, पर जान भी लेती है।' युवाओं में यह प्रवृत्ति सबसे अधिक देखी जाती है कि वे खाली सड़क देखते ही वाहन की गति सीमा पार कर देते हैं। तेज़ रफ़्तार में वाहन पर नियंत्रण पाना असंभव हो जाता है और मामूली सी चूक बड़े हादसे में बदल जाती है।
- **नशे की हालत में ड्राइविंग :** नशा चाहे शराब का हो या किसी अन्य पदार्थ का, यह मस्तिष्क की प्रतिक्रिया करने की क्षमता को धीमा कर देता है। नशे में धुत चालक को दूरी और गति का सही अंदाजा नहीं रहता, जिससे वह न केवल अपनी बल्कि दूसरों की जान का भी दुश्मन बन जाता है।
- **मोबाइल फोन:** एक डिजिटल मौत का फंदा : वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग आज सबसे बड़ा खतरा बनकर उभरा है। एक सेकंड के लिए स्क्रीन पर आई 'नोटिफिकेशन' को देखना आपको हमेशा के लिए खामोश कर सकता है। हेडफोन लगाकर संगीत सुनना भी एकाग्रता को भंग करता है।

सुरक्षा उपकरणों की अनदेखी

हेलमेट और सीट बेल्ट केवल पुलिस के चालान से बचने के लिए नहीं हैं। अध्ययनों से पता चला है कि हेलमेट पहनने से सिर की चोट से होने वाली मौतों में 70% तक की कमी आती है। इसी तरह, सीट बेल्ट कार सवारों को टक्कर के दौरान बाहर फिकने या स्टीयरिंग से टकराने से बचाती है।

आजकल की युवा पीढ़ी में सोशल मीडिया पर प्रसिद्ध होने की एक अंधी दौड़ लगी है। बाइक पर खतरनाक स्टंट करना, हाथ छोड़कर गाड़ी चलाना या चलती गाड़ी से रील बनाना एक 'ट्रेंड' बन गया है। यह रोमांच नहीं, बल्कि आत्महत्या का एक सार्वजनिक प्रयास है। सड़कों पर स्टंट करने वाले युवा यह भूल जाते हैं कि उनकी एक गलती उनके माता-पिता के जीवन भर के आंसुओं का कारण बन सकती है।

कानून: डर बनाम समझदारी

सरकार ने 'संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट' के तहत सड़क सुरक्षा नियमों को अत्यंत सख्त कर दिया है। भारी जुर्माना, लाइसेंस रद्द करना और जेल की सजा—ये सभी उपाय इसलिए किए गए हैं ताकि सड़कों पर अनुशासन बना रहे।

- **जुर्माना बनाम जीवन:** लोग अक्सर भारी जुर्माने की शिकायत करते हैं, लेकिन क्या आपका जीवन 5,000 या 10,000 के जुर्माने से कम कीमती है?
- **आत्म-अनुशासन:** कानून केवल एक सीमा तक काम कर सकता है। जब तक नागरिक स्वयं यह नहीं समझेंगे कि नियमों का पालन उनकी अपनी सुरक्षा के लिए है, तब तक सड़कों पर बदलाव आना कठिन है।

परिवार और समाज की जिम्मेदारी

सड़क सुरक्षा की शिक्षा स्कूल के पाठ्यक्रम से पहले घर के माहौल से शुरू होनी चाहिए।

- **अभिभावकों का रोल:** यदि पिता बिना हेलमेट के घर से निकलता है, तो पुत्र कभी नियमों का पालन नहीं करेगा। माता-पिता को चाहिए कि वे अपने नाबालिग बच्चों को वाहन की चाबी न सौंपें। उन्हें प्यार और सुरक्षा के बीच का अंतर समझना होगा।
- **सामूहिक चेतना:** समाज को सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। 'गुड सेमेरिटन' (नेक मददगार) कानून के तहत अब मदद करने वालों को पुलिस या कोर्ट के चक्कर नहीं काटने पड़ते। घायल को 'गोल्डन ऑवर' (हादसे के पहले 1 घंटे) में अस्पताल पहुँचाना उसकी जान बचा सकता है।

सावधानियाँ, बनती हैं सुरक्षा कवच

सड़क पर चलते समय कुछ बुनियादी नियमों का पालन करके हम बड़े हादसों को टाल सकते हैं:

- **ज़ेब्रा क्रॉसिंग:** पैदल चलने वाले हमेशा सड़क पार करने के लिए निर्धारित स्थान का ही प्रयोग करें।
- **इंडिकेटर का प्रयोग:** मुड़ने से पहले हमेशा संकेत दें ताकि पीछे आने वाला वाहन सतर्क हो सके।
- **दूरी बनाए रखें:** आगे चल रहे वाहन से उचित सुरक्षित दूरी बनाए रखें ताकि अचानक ब्रेक लगने पर टक्कर न हो।
- **मौसम का ध्यान:** कोहरे या बारिश के दौरान हेडलाइट जलाकर चलें और गति अत्यंत धीमी रखें।

जिम्मेदारी ही आपका जीवन है

सड़क सुरक्षा कोई एक दिन का अभियान नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का एक तरीका होना चाहिए। सरकार सड़कें बना सकती है, पुलिस चालान काट सकती है, लेकिन गाड़ी का स्टेयरिंग आपके हाथ में है। आपकी एक छोटी सी लापरवाही केवल आपको ही नहीं, बल्कि आपके पूरे परिवार को बर्बाद कर सकती है।

अंत में, संपादक होने के नाते मैं केवल इतना ही कहूँगा कि घर पर कोई आपका इंतज़ार कर रहा है। वह इंतज़ार केवल शाम की चाय का नहीं, बल्कि आपके जीवन की सलामती का है। अपनी रफ़्तार को संयमित रखें, नियमों को अपना आभूषण बनाएँ और सड़क को रक्त-रंजित होने से बचाएँ।

संकल्प लें:

"सुरक्षित सफर, सुखद जीवन।" "नियमों का पालन, खुद का और अपनों का सम्मान।"

-राहुल हिंदुस्तानी
संपादक, राजधानी चौपाल

नशा नहीं, संस्कृति का संग — होली के पावन पर्व पर एक गंभीर आत्ममंथन

होली केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति की उस जीवंत पहचान का नाम है, जो सदियों से हमारे समाज को एकता के सूत्र में पिरोती आई है। यह वह पर्व है जो मन के भीतर जमी साल भर की कड़वाहट को प्रेम के जल से धो देता है और रिश्तों में फिर से नई मिठास घोल देता है। फागुन की बयार जब चलती है, तो प्रकृति स्वयं रंगों से सराबोर हो जाती है, और यही रंगों की बौछार हमें सिखाती है कि जीवन में विविधता ही उसकी असली सुंदरता है।

परंतु, जैसे-जैसे समय बदल रहा है, हमारे त्योहारों को मनाने के तौर-तरीकों में भी बदलाव आया है। आज एक अत्यंत गंभीर सवाल हमारे सामने यक्ष प्रश्न बनकर खड़ा है—क्या हमारी होली अब भी उतनी ही पवित्र, मर्यादित और अर्थपूर्ण रह गई है, जितनी हमारी महान परंपराओं और शास्त्रों में वर्णित है? या फिर आधुनिकता की अंधी दौड़ में हमने इस उत्सव की मूल आत्मा को ही कहीं पीछे छोड़ दिया है?

नशे का बढ़ता चलन: एक सांस्कृतिक संकट

बीते कुछ वर्षों में हमारे समाज में एक अत्यंत चिंताजनक और भयावह प्रवृत्ति तेजी से बढ़ी है—वह है होली के पावन नाम पर नशे का खुला और भौंडा प्रदर्शन। आज शराब, भांग और अन्य नशीले पदार्थों के सेवन को 'मस्ती' और 'मॉर्डन' होने का प्रतीक बना दिया गया है। गलियों में हुड़दंग मचाते, नशे में धुत युवाओं की टोलियां अब आम दृश्य बन गई हैं।

यह प्रवृत्ति न केवल सार्वजनिक शांति के लिए एक बड़ा खतरा है, बल्कि यह हमारी उस समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर पर भी एक गहरा धब्बा है, जिसने पूरी दुनिया को 'वसुधैव कुटुंबकम' का पाठ पढ़ाया। जब हम त्योहार के नाम पर नशे को बढ़ावा देते हैं, तो हम अनजाने में ही अपनी जड़ों को खोखला कर रहे होते हैं।

पौराणिक जड़ें और पवित्र संदेश: क्या हम भूल गए?

होली का इतिहास हमें केवल रंगों से खेलने की अनुमति नहीं देता, बल्कि यह हमें सत्य की शाश्वत विजय और निस्वार्थ प्रेम के गहन संदेश की याद दिलाता है। पौराणिक कथाओं में भक्त प्रह्लाद की वह अटूट श्रद्धा और विश्वास आज भी प्रासंगिक है, जो हमें सिखाती है कि जब अन्याय और अहंकार की सीमा पार हो जाती है, तो 'होलिका दहन' के रूप में बुराई का अंत निश्चित होता है।

दूसरी ओर, ब्रज की होली, भगवान कृष्ण और राधा की वह अलौकिक रंग-लीला, प्रेम और आपसी सौहार्द का सर्वोच्च प्रतीक है। इन पावन कथाओं और परंपराओं में कहीं भी उन्माद, अभद्रता या चेतना शून्य करने वाले नशे का कोई स्थान नहीं है। तो फिर विचारणीय प्रश्न यह है कि हमने इस सात्विक उत्सव में तामसिक प्रवृत्तियों को प्रवेश कैसे करने दिया?

होली के दिन अक्सर गलियों और चौराहों पर यह वाक्य गूंजता है—"बुरा न मानो होली है।" मूल रूप से यह वाक्य इसलिए बना था ताकि छोटे-मोटे हंसी-मजाक से कोई बुरा न माने और समाज में समरसता बनी रहे। लेकिन आज, दुर्भाग्य से, यह वाक्य असंयम, उच्छृंखलता और घोर अभद्रता को ढंकने का एक सस्ता साधन बन गया है।

नशे की हालत में जब व्यक्ति अपनी सुध-बुध खो बैठता है, तो उसके लिए मज़ाक और दुर्व्यवहार के बीच की महीन रेखा धुंधली हो जाती है। नशे में डूबे लोग इसे अपना अधिकार समझने लगते हैं कि वे किसी के भी साथ बदतमीजी कर सकते हैं। यही वह मानसिक स्थिति है जो अक्सर बड़े झगड़ों, हिंसक झड़पों और महिलाओं के साथ होने वाली अप्रिय घटनाओं का कारण बनती है। क्या हम वाकई यह मान चुके हैं कि साल में एक दिन हमें 'अमानवीय' होने की छूट मिल जाती है?

युवा पीढ़ी और भटकाव का स्टेटस सिंबल

आज का युवा हमारे देश की शक्ति है, उसकी ऊर्जा का केंद्र है। लेकिन जब यही युवा होली जैसे पवित्र अवसर पर पहली बार शराब या नशीले पदार्थों का सेवन केवल इसलिए करता है क्योंकि उसे लगता है कि यह उसके 'स्टेटस' को बढ़ाएगा, तो यह पूरे समाज के लिए खतरे की घंटी है।

अक्सर दोस्तों का दबाव, सोशल मीडिया पर दिखाई जाने वाली बनावटी चमक-धमक और फिल्मों में ग्लैमर के साथ परोसी जाने वाली 'नशे वाली मस्ती' युवाओं को गलत राह पर धकेल देती है। त्योहार की एक दिन की यह 'मस्ती' कई बार उम्र भर की लत में बदल जाती है। युवाओं को यह समझना होगा कि असली 'कूल' होना नशे में नहीं, बल्कि अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखने और मर्यादा में रहकर उत्सव मनाने में है।

नारी सम्मान: समाज की सामूहिक कसौटी

कोई भी समाज कितना सभ्य है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसके त्योहारों में महिलाएं कितनी सुरक्षित और सम्मानित महसूस करती हैं। होली समानता का पर्व है, जहाँ भेद-भाव मिटाए जाते हैं। लेकिन यदि नशे के प्रभाव में आकर कोई व्यक्ति किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुँचाता है, तो वह न केवल एक अपराध है बल्कि हमारे पूरे सामाजिक ढांचे की हार है। नशा इस समस्या को और अधिक विकराल बना देता है क्योंकि यह विवेक को नष्ट कर देता है। हमें एक ऐसा वातावरण बनाना होगा जहाँ हर बहन, बेटी और माँ बिना किसी भय के रंगों के इस उत्सव का आनंद ले सके।

संस्कार और संकल्प

प्रशासन अपनी ओर से गश्त बढ़ाता है, पुलिस तैनात रहती है, लेकिन कानून केवल शरीर को रोक सकता है, मन को नहीं। मन को बदलने का कार्य केवल 'संस्कार' कर सकते हैं। यह जिम्मेदारी हमारे परिवारों की है।

- **प्राकृतिक रंगों का चयन:** रसायनों को त्यागकर प्रकृति के करीब आएं।
- **सामूहिक आयोजन:** व्यक्तिगत हुड़दंग के बजाय मोहल्लों में सांस्कृतिक कार्यक्रम और लोकगीतों के मिलन समारोह हों।
- **नशामुक्त संकल्प:** इस वर्ष प्रत्येक परिवार यह संकल्प ले कि उनके घर के भीतर या बाहर नशे को प्रवेश नहीं मिलेगा।
- **रचनात्मकता:** युवाओं को खेलों और रचनात्मक प्रतियोगिताओं से जोड़ें।

आत्मचिंतन का समय

होली केवल चेहरे पर गुलाल मलने का नाम नहीं है, यह मन के भीतर उजाला करने का अवसर है। जिस तरह हम होलिका दहन की अग्नि में लकड़ियां जलाते हैं, उसी तरह हमें अपने भीतर के अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष और विशेष रूप से नशे की इस कुप्रवृत्ति की आहुति देनी चाहिए।

संपादक होने के नाते नहीं, बल्कि आपके परिवार के एक सदस्य के रूप में मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि आइए, इस बार होली को उसके मूल स्वरूप में वापस लाएं। आइए संकल्प लें कि हम प्रेम के रंगों से तो सराबोर होंगे, लेकिन नशे की गंदगी से दूर रहेंगे।

हमारा संकल्प:

नशा नहीं, संस्कृति का संग।
उन्माद नहीं, उत्सव का रंग।
अपमान नहीं, सम्मान का ढंग।

तभी यह फागुन वाकई मंगलकारी होगा और हमारी आने वाली पीढ़ियां एक सुरक्षित, स्वस्थ और सुसंस्कृत समाज में सांस ले सकेंगी। आप सभी को मर्यादापूर्ण और सुरक्षित होली की हार्दिक शुभकामनाएँ!

-राहुल हिंदुस्तानी
संपादक, राजधानी चौपाल

एआई की दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी ताकत भारत में एआई शिखर सम्मेलन अभी हाल ही में संपन्न हुआ है। इस क्षेत्र में भारत के तेज विकास की बड़ी संभावनाएं हैं, पर यह काम कैसे होगा? आगे का रास्ता किधर जा रहा है? यहां रोजगार और कमाई के मौजूदा आंकड़े बताते हैं कि कदम जमाकर चलने की जरूरत है। हमें उम्मीदों के आकाश में नहीं उड़ना है, जमीनी हकीकत के मुताबिक आगे बढ़ना है। आज देश में इंजीनियरिंग का क्या हाल है? देश की आईटी क्षमता के साथ ही, एआई शक्ति को भी तेजी से बढ़ाना है। पेश है आईटी और एआई क्षेत्र पर निगाह डालती...

आईटी-एआई में कितना काम और कमाई

देश में सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज तमिलनाडु में हैं और वह प्रति वर्ष 1.50 लाख से ज्यादा इंजीनियर दे रहा है। 20 वर्ष पहले वह केवल 36 हजार इंजीनियर दे रहा था। पहले महाराष्ट्र इस मामले में अव्वल था, लेकिन बीते दस वर्ष में तमिलनाडु ने उसे पछाड़ दिया है। अब महाराष्ट्र के बाद क्रमशः आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। ये राज्य प्रति वर्ष एक लाख से ज्यादा इंजीनियर दे रहे हैं, पर इनमें से तीन प्रतिशत ही एआई में कुशल हैं। आज देश को अगर 10 एआई इंजीनियर चाहिए, तो केवल एक कुशल इंजीनियर उपलब्ध है।

भारत के आईटी उद्योग को बाहर से देख रहे लोगों का भी यही मानना है कि यह उद्योग एक निर्णायक दौर से गुजर रहा है। एक पुरानी और बड़ी आशंका है कि एआई के बढ़ते प्रभाव से आईटी क्षेत्र में कई नौकरियां खत्म हो जाएंगी। हालांकि, भारत के आईटी क्षेत्र के दिग्गज यह मानते हैं कि ऐसी आशंकाएं निराधार हैं और यह उद्योग बिना किसी बड़ी कठिनाई के खुद को नए माहौल में ढाल लेगा। यह बहस जल्द ही किसी न किसी रूप में सुलझ जाएगी। इस बीच, यह सवाल पूछना जरूरी है कि इस बहस में आखिर भारत के लिए क्या दांव पर लगा है? एचटी ने इस सवाल का जवाब खोजने के लिए विभिन्न डाटाबेस का व्यापक विश्लेषण किया हैं और पेश हैं उसके कुछ खास पहलू -

आईटी क्षेत्र में रोजगार वृद्धि बहुत पहले ही चरम पर पहुंच गई है। हमने उद्योग संगठन नैसकॉम द्वारा जारी आईटी क्षेत्र के रोजगार आंकड़ों को विभिन्न स्रोतों से संकलित किया है, जिनमें उनके अपने प्रेस ज्ञापन, शोध पत्र और डाटा प्रदाता सीईआईसी शामिल हैं। तमाम रुझानों से स्पष्ट है कि इस क्षेत्र में रोजगार वृद्धि अब अपेक्षाकृत स्थिर है। यह कहना गलत नहीं होगा कि ये आंकड़े साधारण नहीं हैं। 1996 और 2000 के बीच आईटी क्षेत्र में रोजगार 1.8 गुना बढ़े। इसके अगले दशक में तेजी आई, तो आईटी उद्योग को अभूतपूर्व गति मिली, जिससे यहां कर्मचारियों की संख्या आठ गुना से अधिक बढ़कर 23 लाख पर पहुंच गई।

उसके अगले दशक में इस उद्योग में कर्मचारियों की संख्या लगभग दोगुनी बढ़ी, हालांकि, इस बार इसका आधार कहीं अधिक बड़ा था। 2020 से 2025 की अवधि में कर्मचारियों की संख्या में महज 1.3 गुना वृद्धि देखी गई। स्पष्ट रूप से 2000 का दशक या इस सदी का पहला दशक आईटी क्षेत्र में सबसे अच्छा बीता था। क्या इधर आईटी के विकास की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई है? क्या एआई ने आईटी के विकास को प्रभावित किया है? कम से कम बड़ी कंपनियों के आंकड़े तो हमें यही बताते हैं।

नैसकॉम द्वारा जारी किए गए केवल रोजगार संबंधी आंकड़ों पर निर्भर रहने के बजाय, एचटी ने सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) द्वारा तैयार किए गए डाटाबेस में कंपनी/क्षेत्रवार डाटा का भी अध्ययन किया है, जिसमें 38,000 सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध कंपनियां शामिल हैं। कुल मिलाकर, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 5,200 फर्मों या कंपनियों के पास साल 2024 में लगभग 22 लाख कर्मचारी थे, यह नैसकॉम के अनुमान से कम है।

बड़ी कंपनियों में स्थिर हुआ रोजगार

निफ्टी आईटी इंडेक्स की दस कंपनियों - टीसीएस, इंफोसिस, एचसीएल, विप्रो, एलटीआई माइंडट्री, टेक महिंद्रा, परसिस्टेंट सिस्टम्स, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, एमफैसिस और कोफोर्ज - ने 2024 में इन 22 लाख कर्मचारियों में से 18 लाख को रोजगार दे रखा था। चूंकि पर्याप्त डाटा केवल पिछले 10 वर्षों के लिए उपलब्ध है, इसलिए 2020 से पहले की अवधि तक जाना और विश्लेषण करना मुश्किल है। हालांकि, उपलब्ध डाटा से पता चलता है कि महामारी के तुरंत बाद के समय में थोड़ी वृद्धि को छोड़कर, रोजगार वृद्धि आईटी सेक्टर में काफी हद तक स्थिर ही रही है।

हालांकि, यहां जरूरत केवल बड़ी कंपनियों को देखने की नहीं है। बड़े पैमाने पर छोटी कंपनियां भी इस उद्योग में आगे आई हैं और उन्होंने बड़ी संख्या में रोजगार दिए हैं। ऐसे में, समग्रता में इस क्षेत्र में भारत की स्थिति को ठीक माना जा रहा है। बहरहाल, हमें यह सोचना होगा कि हम एआई के दौर में भी रोजगार को कैसे बढ़ा सकते हैं?

प्रबंधन में एआई को मिले बढ़ावा

एआई के मामले में कुशल इंजीनियर की ही नहीं, हमें एआई में कुशल प्रबंधकों की भी जरूरत है। अंततः ज्यादातर कंपनियों में प्रबंधक ही इंजीनियरों से काम लेते हैं। ऐसे में, प्रबंधक या बिजनेस लीडर का एआई में पारंगत होना बहुत जरूरी है। एक सर्वेक्षण के मुताबिक, भारतीय बिजनेस स्कूल शिक्षण, अनुसंधान और पाठ्यक्रम निर्माण में जनरेटिव एआई को तेजी से अपना रहे हैं। फिर भी केवल 51 प्रतिशत संकाय सदस्य ही बिजनेस स्कूल के छात्रों पर एआई के सकारात्मक प्रभाव को लेकर आश्वस्त हैं। इसके अलावा, केवल 7 प्रतिशत ही इसके विशेषज्ञ उपयोगकर्ता हैं।

एमबीए यूनिवर्स डॉट कॉम द्वारा भारत के शीर्ष बिजनेस स्कूलों (आईआईएम सहित) के 235 संकाय सदस्यों के बीच किए गए सर्वेक्षण में जनरेटिव एआई द्वारा प्रबंधन शिक्षा को आकार देने के तरीके का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। सर्वेक्षण के अनुसार, 51 प्रतिशत संकाय सदस्यों ने छात्रों के विकास में एआई के सकारात्मक प्रभाव की बात मानी है, जबकि आधे से अधिक को उम्मीद है कि अगले 12 महीनों में शिक्षण, पाठ्यक्रम और अनुसंधान में एआई की भूमिका बढ़ेगी। 55 प्रतिशत संकाय सदस्य एआई के मध्यम स्तर के उपयोगकर्ता हैं, जबकि 7 प्रतिशत स्वयं को विशेषज्ञ मानते हैं।

सर्वेक्षण में यह भी पाया गया है कि एआई उपकरणों में, चैटजीपीटी को शिक्षण संबंधी गतिविधियों के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक माना गया। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट और परप्लेक्सिटी का स्थान रहा, जबकि गूगल जेमिनी और क्लाउड को मध्यम रेटिंग मिली। मेटा एआई को प्रासंगिकता में सबसे कम रेटिंग मिली। अब बिजनेस स्कूल में जो प्रबंधक तैयार किए जा रहे हैं, उन्हें एआई में पारंगत करना होगा। नेतृत्व करने वाले उद्यमियों को भी एआई में कुशल होना पड़ेगा।

एआई का लीजिए पूरा लाभ

ओपनएआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने चेतावनी दी है कि एआई केवल वैज्ञानिक प्रगति को ही नहीं, पूरी अर्थव्यवस्था को संचालित करने लगेगा। शिक्षा पूरी तरह से बदल जाएगी। स्वास्थ्य सेवा पूरी तरह से बदल जाएगी। काम करने का मतलब ही पूरी तरह बदल जाएगा। कंपनियां कुछ लोगों और एक विशाल डाटा सेंटर के साथ अविश्वसनीय रूप से नए प्रकार के मूल्य का निर्माण करने लगेंगी। एआई अर्थव्यवस्था और जीवन स्तर में सुधार लाने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक हो गया है। यह एक ऐसा आर्थिक इंजन है, जो नई क्षमताओं को दुनिया के सामने ला रहा है। आने वाली पीढ़ी लोगों की जरूरतों को ज्यादा बेहतर ढंग से समझ पाएगी। आने वाली पीढ़ी लोगों के साथ बातचीत करने, उन्हें प्रेरित करने, रचनात्मक विचार पेश करने, तेजी से अनुकूलन करने और मूल्य सृजित करने के तरीके को ज्यादा बेहतर ढंग से समझ पाएगी।

एआई में वेतन का हाल बेहतर

भारत की बात करें, तो शुरुआती स्तर के ट्रेनी एआई इंजीनियर का मासिक वेतन 40,000 रुपये से 70,000 रुपये तक होता है, जिसमें ज्यादातर फ्रेशर्स को 50 से 60 हजार रुपये के बीच वेतन मिलने लगा है। ये इंजीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या डाटा एनालिसिस का काम करते हैं। एक या दो वर्ष के अनुभव के बाद प्रतिमाह वेतन दो लाख रुपये तक पहुंच जाता है। एक औसत अनुभवी एआई इंजीनियर को प्रति माह 3.5 लाख रुपये वेतन मिलने लगा है। वैसे, भारत से विदेश जाने वाले आईटी या एआई इंजीनियर भी बहुत हैं, भारत की तुलना में विदेश में दो गुना से चार गुना अधिक वेतन मिलने की संभावना रहती है। विदेशी कंपनियां अनुभवी भारतीय इंजीनियरों को तरजीह देती हैं। यहां यह ध्यान देने की बात है कि अमेरिका में 42 टॉप एआई स्टार्टअप में से 9 का नेतृत्व या प्रबंधन भारतीय इंजीनियर-उद्यमियों के हाथ में है। वहां ज्यादातर एआई कंपनियों में ठीक-ठाक संख्या में भारतीय इंजीनियर अच्छे पदों पर कार्यरत हैं।

प्रतिभा पलायन रोकना जरूरी

भारत में एआई की प्रतिभाओं को रोकना जरूरी है। एक अनुमान के अनुसार, भारत के करीब 100 एआई स्टार्टअप ज्यादा सुविधा और कमाई की वजह से या तो अमेरिका जा चुके हैं या जाने की तैयारी में हैं। जिन भारतीय कंपनियों ने अपने देश में अपना कारोबार फैला लिया है, वे भी अमेरिका और यूरोपीय देशों में अपने लिए बड़ा बाजार या अवसर तलाश रही हैं। ज्यादा चिंता की बात यह है कि भारतीय कंपनियां ही नहीं, बल्कि उनके संस्थापक भी विदेश में बसने को तरजीह दे रहे हैं। जाहिर है, भारत में एआई के विकास को बढ़ावा देने के लिए ज्यादा बेहतर माहौल की जरूरत है। भारत भले ही एआई की तीसरी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन उसे अपनी ताकत को सहेजने के लिए बड़े प्रयासों या अभियानों की जरूरत है। साथ ही, केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से भी एआई उद्योग को ज्यादा मदद की आशा है। गंभीरता से विचार करना होगा कि भारतीय उद्यमियों को भारत में रुकने के लिए क्या चाहिए?

बढ़ती चुनौतियों पर रहे नजर

सॉफ्टवेयर सेवा उद्योग में कार्यरत कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित रखना होगा। वैसे, निफ्टी में शामिल आईटी कंपनियों में कर्मचारियों की कुल संख्या कोविड-पूर्व स्तर से काफी अधिक है। हालांकि, उन वर्षों में और उसके बाद भी राजस्व वृद्धि के साथ-साथ भर्ती प्रक्रिया चलती रही है, लेकिन अब अनिश्चितता कहीं अधिक है। दिसंबर में समाप्त तिमाही के लिए अपनी नवीनतम रिपोर्ट में, टीसीएस ने लगभग 30,000 कर्मचारियों की शुद्ध कटौती दर्ज की है। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट में कहा गया है, यदि उद्योग को इस स्थिति (वित्त वर्ष 2015-2019 की अवधि में देखी गई गिरती मार्जिन और स्थिर उत्पादकता) से बचना है, तो भर्ती प्रक्रिया को राजस्व वृद्धि से कुछ हद तक अलग करना होगा। इससे प्रति कर्मचारी राजस्व में वृद्धि होगी और मार्जिन बनाए रखने में मदद मिलेगी।

ऐसा लगता है, कई बड़ी भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनियों ने अत्याधुनिक तकनीक में निवेश करने में चूक की है और इसका बोझ कर्मचारियों पर पड़ने की आशंका है। हो सकता है, एआई के प्रभावों को बढ़ा-चढ़ाकर बताया जा रहा हो। कंपनियों को मजबूती का परिचय देना होगा। छंटनी करने या छंटनी का रोना रोने वाली भारतीय कंपनियों को छवि की भी चिंता करनी चाहिए। भारतीय कंपनियां सुरक्षित रोजगार देंगी, तो इससे उन्हें अच्छे मानव संसाधन और धन, दोनों तरह से लाभ होगा।

गुणवत्ता : बिहार, झारखंड और दिल्ली आगे

बिहार में 80 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, इसके अलावा बिहार के छात्र देश भर में पढ़ते हैं। गुणवत्ता के मामले में देश में बिहार, झारखंड और दिल्ली के इंजीनियर को ज्यादा पारंगत पाया जाता है। तमिलनाडु ज्यादा इंजीनियर देता है, पर बिहार-झारखंड रोजगार योग्य इंजीनियर देने में आगे हैं। स्थानीय स्तर पर बिहार अभी प्रति वर्ष करीब 1400 इंजीनियर और 16 हजार से ज्यादा डिप्लोमा इंजीनियर देता है। बिहार में अभी 30 के करीब सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं और पूरी इंजीनियरिंग शिक्षा में गुणवत्ता सुधार की जरूरत है, ताकि स्थानीय स्तर पर भी तकनीक और एआई का लाभ राज्य को मिले।

उत्तर प्रदेश इंजीनियर देने में 5वें स्थान पर

उत्तर प्रदेश इंजीनियर देने में देश में पांचवें स्थान पर है। साल 2005 में उत्तर प्रदेश केवल 29,809 इंजीनियर देता था, लेकिन अब 1,15,627 इंजीनियर देता है। साल 2015 में यह राज्य इंजीनियर देने के मामले में सातवें स्थान पर पहुंच गया था, लेकिन बीते दस वर्ष में इसने अपना पांचवां स्थान फिर हासिल कर लिया है। यहां इंजीनियरिंग कॉलेज की संख्या 600 से ज्यादा है। इसमें कोई दोराय नहीं कि राज्य में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने की जरूरत है, ताकि स्थानीय स्तर पर तकनीक और एआई का पूरा लाभ इस बड़े राज्य व इसके युवाओं को मिल सके।

भारत में एआई की प्रतिभाओं को रोकना जरूरी है। एक अनुमान के अनुसार, भारत के करीब 100 एआई स्टार्टअप ज्यादा सुविधा और कमाई के लिए या तो अमेरिका जा चुके हैं या जाने की तैयारी में हैं। जिन भारतीय कंपनियों ने अपने देश में अपना कारोबार फैला लिया है, वे भी अमेरिका और यूरोपीय देशों में अपने लिए बड़ा बाजार या अवसर तलाश रही हैं।

ज्यादा चिंता की बात यह है कि भारतीय कंपनियां ही नहीं, बल्कि उनके संस्थापक भी विदेश में बसने को तरजीह दे रहे हैं। जाहिर है, भारत में एआई के विकास को बढ़ावा देने के लिए ज्यादा बेहतर माहौल बनाने की जरूरत है।

सड़कों पर उतरेगा 'चलता-फिरता आलीशान महल'

मर्सिडीज-बेंज ने 1.40 करोड़ में लॉन्च की नई V-क्लास

नई दिल्ली (राजधानी चौपाल)| लग्जरी कार निर्माता कंपनी मर्सिडीज-बेंज इंडिया ने भारतीय सड़कों पर अपना जलवा बिखेरने के लिए बहुप्रतीक्षित लग्जरी MPV (मल्टी पर्पस व्हीकल) वी-क्लास (V-CLASS) का अपडेटेड 2026 मॉडल लॉन्च कर दिया है। साल 2022 में भारतीय बाजार से विदा लेने के बाद, वी-क्लास ने अब और भी अधिक भव्यता, अत्याधुनिक फीचर्स और बेहतर सुरक्षा मानकों के साथ वापसी की है। कंपनी ने इस 'सुपर लग्जरी वैन' की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 1.40 करोड़ रुपये निर्धारित की है।

मार्च के अंत से शुरू होगी डिलीवरी, पहली बार पेट्रोल इंजन की एंट्री

मर्सिडीज-बेंज इंडिया ने इस बार भारतीय ग्राहकों की बदलती प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा बदलाव किया है। इस मॉडल के साथ पहली बार भारत में पेट्रोल इंजन का विकल्प पेश किया गया है, जो न केवल स्मूथ और शांत ड्राइविंग अनुभव प्रदान करता है, बल्कि बढ़ते प्रदूषण मानकों के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। कंपनी के अनुसार, नई वी-क्लास की बुकिंग शुरू हो चुकी है और इसकी डिलीवरी मार्च 2026 के अंत तक शुरू कर दी जाएगी। प्रीमियम वैन सेगमेंट में इस कार का सीधा मुकाबला लेक्सस LM और टोयोटा वेलफायर जैसी स्थापित लग्जरी कारों से होगा।

एक्सटीरियर: AMG लाइन के साथ स्पोर्टी और धाकड़ लुक

नई वी-क्लास का डिजाइन इसे भीड़ से अलग बनाता है। कंपनी ने इसे 3430MM के 'एक्स्ट्रा-लॉन्ग-व्हीलबेस' के साथ उतारा है, जो वर्तमान में भारत में बिकने वाली मर्सिडीज की किसी भी अन्य यात्री कार के मुकाबले सबसे ज्यादा है। इसके फ्रंट लुक में कंपनी की सिग्नेचर 'थ्री-पॉइंटेड स्टार' वाली ग्रिल और मल्टी-बीम LED हेडलाइट्स दी गई हैं, जो इसे एक प्रभावशाली चेहरा प्रदान करती हैं। साइड प्रोफाइल की बात करें तो इसमें 18-इंच के स्टाइलिश डुअल-टोन अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। सबसे खास इसके पिछले दरवाजे हैं, जो पूरी तरह से इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड हैं और हैंडल खींचते ही पीछे की ओर स्लाइड होकर खुलते हैं, जिससे कार में प्रवेश करना और बाहर निकलना बेहद आसान हो जाता है।

इंटीरियर: थिएटर जैसा साउंड और प्राइवेट जेट सा अहसास

वी-क्लास के अंदर कदम रखते ही आपको किसी लग्जरी प्राइवेट जेट या थिएटर में होने का अहसास होता है। मर्सिडीज ने इसमें 15 स्पीकर वाला बर्मेस्टर साउंड सिस्टम दिया है, जो सराउंड साउंड के साथ थिएटर जैसा ऑडियो आउटपुट प्रदान करता है। सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इसमें 360-डिग्री कैमरा सिस्टम दिया गया है, जो संकरी सड़कों पर पार्किंग और ड्राइविंग को आसान बनाता है। इसके अलावा, कार का पिछला कांच अलग से खुलने की सुविधा के साथ आता है, जिससे छोटे सामान या बैग को पूरा टेलगेट खोले बिना ही अंदर रखा जा सकता है।

मिलेनियम सिटी के शौकीनों के लिए पांच आकर्षक रंग

गुरुग्राम और दिल्ली-एनसीआर जैसे क्षेत्रों में लग्जरी कारों के शौकीनों को लुभाने के लिए कंपनी ने इसे पांच प्रीमियम कलर ऑप्शंस में पेश किया है। इसमें ऑब्सीडियन ब्लैक, हाई-टेक सिल्वर, अल्पाइन ग्रे, सोडालाइट ब्लू और क्रिस्टल वाइट शामिल हैं। उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि 'वेड इन इंडिया' और कॉर्पोरेट ट्रैवल के बढ़ते चलन के कारण इस लग्जरी की मांग बाजार में काफी रहने वाली है।

एपल ने चला 'किफायती' दांव: मार्केट में उतारा आईफोन 17E और M4 चिप वाला नया आईपैड एयर

नई दिल्ली (राजधानी चौपाल)| दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी एपल ने भारतीय समयनुसार सोमवार, 2 मार्च को अपने पिटारे से दो बड़े धमाके किए हैं। कंपनी ने अपनी लेटेस्ट 17 सीरीज के तहत सबसे किफायती स्मार्टफोन आईफोन 17E को पेश कर दिया है। इसके साथ ही, टैबलेट लवर्स के लिए अब तक का सबसे शक्तिशाली आईपैड एयर (M4 प्रोसेसर) भी लॉन्च किया गया है। इन दोनों ही गैजेट्स की शुरुआती कीमत 64,900 तय की गई है।

कीमत और ऑफर्स: छात्रों के लिए बड़ी राहत : आईफोन 17E और नए आईपैड एयर के बेस वैरिएंट (256GB) की कीमत 64,900 है, जबकि हायर वैरिएंट 84,900 में उपलब्ध होगा। एपल ने छात्रों का विशेष ख्याल रखते हुए आईपैड एयर पर बड़ा डिस्काउंट दिया है, जिसके बाद यह उन्हें मात्र 59,900 में मिलेगा। इच्छुक ग्राहक इन प्रोडक्ट्स की बुकिंग 4 मार्च की शाम 7:45 बजे से कर सकेंगे, जबकि मार्केट में इनकी बिक्री 11 मार्च से शुरू होगी।

डिजाइन और मजबूती: एपल ने आईफोन 17E के साथ मजबूती के नए मानक स्थापित किए हैं। फोन के फ्रंट में सिरेमिक शील्ड 2 दी गई है, जो इसे स्क्रैच से 3 गुना ज्यादा सुरक्षित बनाती है। बैक पैनल पर 'मैट' फिनिश के साथ बेहतरीन ग्रिप दी गई है। खास बात यह है कि इसमें भी अब 'एक्शन बटन' और USB टाइप-C पोर्ट स्टैंडर्ड के तौर पर मिलेगा।

डिस्प्ले: 6.1-इंच की सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले, जो 1200 निट्स की ब्राइटनेस के साथ तेज धूप में भी क्रिस्टल क्लियर दिखती है।

प्रोसेसर: इसमें 3NM तकनीक पर आधारित लेटेस्ट A19 चिपसेट लगा है। कंपनी का दावा है कि यह आईफोन 11 से दोगुना और गेमिंग के मामले में बेमिसाल है।

कैमरा और 'एपल इंटेलिजेंस': फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए इसमें 48MP का फ्यूजन कैमरा दिया गया है। यह कैमरा 'इन-सेंसिंग क्रॉपिंग' के जरिए बिना क्वालिटी खोए 2X ऑप्टिकल ज़ूम देने में सक्षम है। यह डिवाइस IOS 26 पर संचालित है, जिसमें कॉल स्क्रीनिंग और लाइव ट्रांसलेशन जैसे एडवांस 'एपल इंटेलिजेंस' फीचर्स दिए गए हैं।

न्यूज ब्रीफ

शाओमी पैड 8 टैबलेट 9200mAh की बैटरी के साथ आएगा: 3.2K रेजोल्यूशन वाली 11.2-इंच एमोलेड डिस्प्ले

नई दिल्ली (राजधानी चौपाल)| चाइनीज टेक कंपनी शाओमी भारतीय बाजार में शनिवार को अपना अगला फ्लैगशिप टैबलेट शाओमी पैड 8 लॉन्च करने जा रही है। लॉन्चिंग इवेंट शाम 6:30 बजे होगा। इवेंट में शाओमी 17 और 17 अल्ट्रा स्मार्टफोन्स भी पेश किए जाएंगे।

यह टैबलेट गेमिंग और मल्टीटास्किंग के शौकीनों के लिए पावरफुल स्पेसिफिकेशन्स के साथ आएगा। इसमें स्नैपड्रैगन 8S जेन 4 प्रोसेसर, 3.2K रेजोल्यूशन वाली 11.2-इंच एमोलेड डिस्प्ले और 9200MAH बैटरी मिलेगी। कंपनी टैबलेट को दो वर्जन में पेश करेगी। इसमें एक स्टैंडर्ड डिस्प्ले वर्जन होगा, जबकि दूसरा नैनो टेक्स्चर डिस्प्ले के साथ आएगा। इसकी शुरुआती कीमत 30 हजार रुपए हो सकती है। इसकी सीधी टक्कर वनप्लस पैड गो 2 और सैमसंग गैलेक्सी टैब S10 लाइट से होगी। डिजाइन के मामले में शाओमी पैड 8 काफी मॉडर्न और स्लिम है। यह मात्र 5.75 MM पतला है और इसका वजन लगभग 485 ग्राम है, जिससे इसे लंबे समय तक हाथ में पकड़ना आसान है। फ्रंट में बहुत पतले बेजल्स दिए गए हैं। इसका बैक पैनल क्लीन है, जहां एक स्क्वायर कैमरा मॉड्यूल दिया गया है। इसे प्रीमियम शेड्स में लाया जा सकता है। यह शाओमी के 'फोकस पेन प्रो' स्टायलस और बैकपैक कीबोर्ड को सपोर्ट करता है, जिसमें जेस्चर इनेबल्ड टचपैड दिया गया है। इसमें 3.2K रेजोल्यूशन वाली 11.2 इंच की स्क्रीन मिलेगी, जो 144HZ रिफ्रेश रेट पर काम करती है। आंखों की सेफ्टी के लिए इसमें TÜV रीनलैंड आई प्रोटेक्शन और DC डिमिंग फीचर दिया गया है। फोटोग्राफी और स्कैनिंग के लिए रियर में 13MP का कैमरा और वीडियो कॉलिंग के लिए 8MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। इसमें स्नैपड्रैगन 8S जेन 4 प्रोसेसर दिया गया है। यह चिपसेट गेमिंग और क्रिएटिव काम के लिए नियर-फ्लैगशिप पावर देता है। इसमें 12GB तक की रैम और 256GB तक की इंटरनल स्टोरेज मिल सकती है।

एडवेंचर और लग्जरी का 'ट्रैक' पर मिलन

जीप ने 35.95 लाख में लॉन्च किया मेरिडियन का स्पेशल एडिशन

नई दिल्ली (राजधानी चौपाल)| एडवेंचर और प्रीमियम ड्राइविंग के शौकीनों के लिए जीप इंडिया ने एक बड़ी सौगात पेश की है। कंपनी ने अपनी लोकप्रिय 7-सीटर एसयूवी (SUV) मेरिडियन का नया और खास 'ट्रैक एडिशन' (TRACK EDITION) भारतीय बाजार में आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है। यह एक लिमिटेड-रन मॉडल है, जिसे मेरिडियन के टॉप-स्पेक 'ओवरलैंड' ट्रिम पर आधारित किया गया है। स्पोर्टी डिकल्स और प्रीमियम फीचर्स से लैस यह एसयूवी अब पहले से कहीं अधिक आक्रामक और मस्कुलर नजर आती है।

जीप इंडिया ने इस स्पेशल एडिशन की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 35.95 लाख (4X2 ऑटोमैटिक वैरिएंट) तय की है। वहीं, इसके अधिक शक्तिशाली 4X4 ऑटोमैटिक वैरिएंट की कीमत 37.82 लाख रखी गई है। अपने स्टैंडर्ड ओवरलैंड मॉडल के मुकाबले यह मात्र 34,000 महंगा है, जो इसमें मिलने वाले कॉस्मेटिक और फीचर अपडेट्स को देखते हुए काफी आकर्षक लगता है। कंपनी ने इसकी बुकिंग अपनी आधिकारिक वेबसाइट और डीलरशिप्स पर शुरू कर दी है। इसके साथ ग्राहकों को 9,200 का अतिरिक्त 'AXS पैक' भी लेना होगा।

मेरिडियन ट्रैक एडिशन को स्टैंडर्ड मॉडल से अलग दिखाने के लिए कंपनी ने इसके बाहरी हिस्से में कई 'पियानो ब्लैक' एलिमेंट्स जोड़े हैं। कार की सिग्नेचर फ्रंट ग्रिल, बैज और साइड मोल्डिंग्स पर ग्लॉसी ब्लैक फिनिश दी गई है, जो इसे प्रीमियम लुक प्रदान करती है। सबसे बड़ा आकर्षण इसके बोनट पर दिया गया नया डिकल (ग्राफिक) और टेलगेट पर लगी 'ट्रैक एडिशन' की ब्रांडिंग है। ये बदलाव कार को एक स्पोर्टी कैरेक्टर देते हैं, जो इसे सड़क पर भीड़ से अलग खड़ा करते हैं।

केबिन के भीतर कदम रखते ही आपको एक नई और लग्जरी दुनिया का अहसास होता है। डैशबोर्ड को प्रीमियम सुएड फैब्रिक और कंट्रास्ट स्टिचिंग के साथ सजाया गया है। सीटों पर डुअल-टोन लेदरेट और सुएड अपहोल्स्ट्री का मिश्रण है, जिसमें क्विल्टेड स्टिचिंग दी गई है। केबिन को 'डार्क एस्प्रेसो' एक्सेंट और पियानो ब्लैक बेजल्स से संवारा गया है। इसके अलावा, फ्लोर मैट्स और डैशबोर्ड पर 'ट्रैक एडिशन' का लोगो इस लिमिटेड मॉडल की विशिष्टता को दर्शाता है।

तकनीकी तौर पर यह एसयूवी बेहद एडवांस है। इसमें 10.1-इंच का विशाल टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 10.25-इंच का डिजिटल क्लस्टर दिया गया है। आरामदायक सफर के लिए इसमें पैनोरमिक सनरूफ, मेमोरी फंक्शन वाली वेंटिलेटेड सीट्स और एल्पाइन का प्रीमियम ऑडियो सिस्टम मिलता है। सुरक्षा के मोर्चे पर, इसमें लेवल-2 ADAS दिया गया है, जिसमें लेन कीप असिस्ट, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे फीचर्स शामिल हैं।

हमारा शरीर कई अनकहे, अनसुलझे घावों का चलता-फिरता घर है, जो हमें खुलकर जीने से रोकते हैं। क्या कभी आपने अपनी बेचैनी, बेवजह के गुस्से, नियंत्रण की भावना या शरीर के किसी पुराने दर्द को समझने की कोशिश की है? यह लेख हमें उस यात्रा पर ले जाता है, जहां हम अपने तन से जुड़कर बरसों पुराने अदृश्य बोझ से हमेशा के लिए आजाद हो सकते हैं...

तन को न बनाएं तनाव का घर

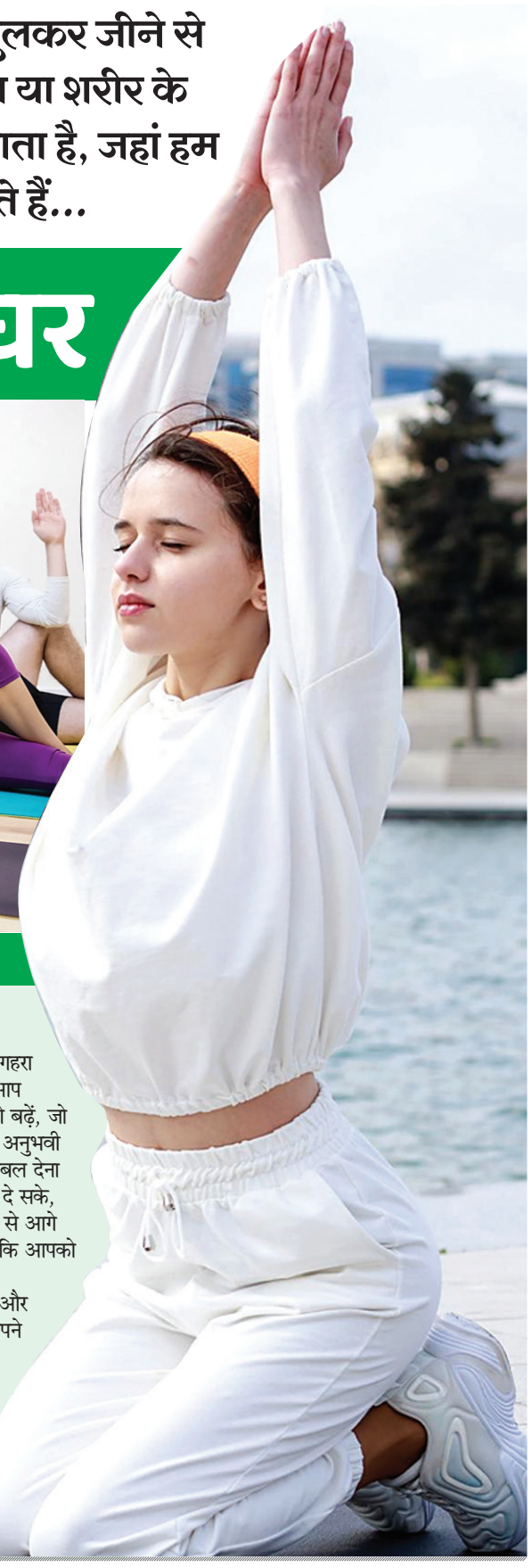

कुछ साल पहले मैं अपनी 'स्त्री शक्ति' को समझने के लिए एक ऑनलाइन कोर्स कर रही थी। बरसों तक बच्चों की परवरिश और कमर के पुराने दर्द की वजह से मैं अपने ही शरीर से कटी-कटी सी महसूस करती थी। उस दिन मैं उत्साहित थी और खुद से दोबारा जुड़ने के लिए तैयार थी। दोपहर का वक्त था। मैंने एक मधुर पुर्तगाली संगीत लगाया और नाचना शुरू किया। मैं अपनी गरिमा को महसूस कर पा रही थी कि अचानक मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरा रोना रुक ही नहीं रहा था। मेरे भीतर एक गहरा और खौफनाक एहसास जागा- जैसे मैं कहीं भी सुरक्षित नहीं हूं। मैं बुरी तरह डर गई थी। मैंने नाचने की कोशिश की, लेकिन मेरा शरीर कांप रहा था। मेरा मन किया कि बस एक गेंद की तरह सिमट जाऊं और कहीं छिप जाऊं। मैं उलझन में थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्यों रो रही हूं? मेरे पास कोई ऐसी याद या घटना नहीं थी, जिसे मैं उस डर से जोड़ पाती।

तन से जुड़ी मन की सेहत

कुछ समय बाद जब मैंने 'न्यूरो इमोशनल कोचिंग' की ट्रेनिंग ली, तब मुझे समझ आया कि उस दिन क्या हुआ था। मेरी युवावस्था में एक ऐसी घटना घटी थी, जो बहुत दर्दनाक और उलझन भरी थी। मैंने कभी किसी को नहीं बताया। उस वक्त मैं बहुत अकेली थी और गहरे अपराध बोध से भरी थी। मैंने उन भावनाओं को दबा दिया था, लेकिन वह सब एक गहरे सदमे में बदल गया। ट्रॉमा हमारे शरीर में जमा हो जाता है और हमें पूरी तरह आजाद होकर जीने से रोकता है। जब आप इसे पहचानना सीख जाते हैं, तो यह कई रूपों में सामने आता है। ज्यादातर लोग, यहां तक कि दशकों तक मैं भी शरीर में छिपे पुराने जख्म नहीं देख पाती थी।

अक्सर हम ट्रॉमा या सदमे को बड़ी दुर्घटनाओं से ही जोड़कर देखते हैं, लेकिन यह रोजमर्रा की जिंदगी में इन रूपों में भी दिख सकता है :

- कुछ खास स्थितियों या लोगों से हद से ज्यादा बचना
- बिना किसी स्पष्ट कारण के घबराहट या बेचैनी रहना
- शरीर में पुराना दर्द या ऐसी बीमारियां, जिनका इलाज नहीं मिल रहा
- छोटी सी बात पर बहुत तेज गुस्सा या प्रतिक्रिया देना
- अपने ही शरीर में असहज महसूस करना

गहरे सदमों को समझिए...

ट्रॉमा किसी ऐसे अनुभव को कहा जाता है, जिससे तीव्र भावनाएं और असहनीय दर्द शामिल होता है। दुख या तकलीफ के ऐसे क्षण, जिन्हें सहते समय आप बिल्कुल अकेले और बेसहारा थे। गैबर मोट कहते हैं, 'ट्रॉमा एक मानसिक घाव है, जो आपको मनोवैज्ञानिक रूप से सख्त बना देता है और फिर आपके विकास में बाधा डालता है। यह आपको दर्द देता है और आप उस दर्द के वश में होकर काम करते हैं। यह डर पैदा करता है और अब आप डर के साए में फैसले लेते हैं। मेरा शरीर उस पुराने दर्द को तिजोरी में बंद किए बैठा था। वह उसे भूला नहीं था, उसे सब याद था।

जब भी मैं अपने शरीर से गहरा जुड़ाव महसूस करती, वह दर्द बार-बार 'असुरक्षा' के एक गहरे एहसास के रूप में सामने आता था। हम अपने शरीर में कहां तनाव और दर्द महसूस करते हैं, यह अक्सर संकेत है कि हमारे अनसुलझे घाव कहां छिपे हैं। जब भी मैं नृत्य करती, गहरे श्वास का अभ्यास करती तो यह दर्द अचानक उभर जाता। पुराने घाव हमारे व्यवहार को कई तरह से प्रभावित कर सकते हैं, जैसे-

- वह व्यक्ति जिसकी मां बहुत बेचैन रहती थी, वह दुनिया में इतना असुरक्षित महसूस करता है कि सब कंट्रोल करना चाहता है।
- वह मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति, जिसका शरीर लगातार दर्द में रहता है, एक बीमारी ठीक होती है, तो दूसरी जगह दर्द शुरू हो जाता है। जिसे बचपन में हमेशा डांटा और कोसा गया है।
- वह महिला जो हमेशा अकेली रहती है, जिसके माता-पिता हमेशा उसे हीन महसूस कराते थे। बाहर से लगता है कि उसे कोई साथी नहीं मिल रहा, पर असल में वह आत्मीयता से बचती है।
- मेरे बीते अनुभवों ने कई चीजों में असुरक्षा का अहसास पैदा कर दिया था- हवाई जहाज में उड़ना मुझे घबराहट देता था, कोई भी साहसिक गतिविधि मेरे लिए मना थी। कोई भी ऐसी स्थिति,जहां मुझे लगे, मेरा शरीर मेरे नियंत्रण से बाहर है और कमजोर है, वह मेरे नर्वस सिस्टम को हिला देती थी।
- कुल मिलाकर, सदमा वह नहीं है, जो आपके साथ होता है, बल्कि वह है, जो उस घटना के कारण आपके भीतर घटित होता है।

शरीर ही है समाधान

हमारा शरीर बीते हुए दर्दनाक पलों की यादों और संवेदनाओं का एक चलता-फिरता बैंक हैं, लेकिन हमारा शरीर वह जगह भी है, जहां हम सबसे गहरी, सबसे तीव्र और मुक्त कर देने वाली आजादी पा सकते हैं।

- **मुक्ति की राह :** जरूरी कदम
- **खुद के प्रति करुणा:** जब पुरानी भावनाएं उभरें, तो उनसे लड़ें नहीं। शांत बैठकर उन्हें महसूस करें और खुद को सांत्वना दें।
- **सोमैटिक हीलिंग:** कभी-कभी दर्द इतना गहरा होता है कि हम अकेले नहीं संभाल पाते। आप उपचार की किसी ऐसी पद्धति के साथ आगे बढ़ें, जो तन और मन के जुड़ाव से जुड़ी हो। किसी अनुभवी या ऐसे व्यक्ति की मदद लें, जो आपको संबल देना जानता हो और आपको भावनात्मक सुरक्षा दे सके, ताकि आप घाव भरने की दिशा में सहजता से आगे बढ़ें। एक सही विशेषज्ञ यह भी समझाएगा कि आपको क्या उम्मीद करनी चाहिए।
- **शरीर से जुड़ाव:** हमारा शरीर ही चाबी है और एक अद्भुत मार्गदर्शक है। शरीर के साथ अपने रिश्ते को दोबारा बेहतर बनाने की शुरुआत शरीर में दबे हुए उस पुराने बोझ को उतारने से होगी, जिसे ढोते-ढोते हम थक चुके हैं। योग, नृत्य, मसाज या गहरी सांस लेने की प्रक्रियाएं दबे हुए भावनात्मक बोझ को बाहर निकालने में मदद करती हैं।

होली पर मिलावटी मावे से सावधान हो सकते हैं ये हेल्थ रिस्क...

होली का त्योहार भारतीय संस्कृति में रंगों, खुशियों और आपसी मेल-मिलाप का प्रतीक है। इस उत्सव की कल्पना बिना मिठाइयों, विशेषकर 'गुझिया' के बिना अधूरी है। लेकिन जैसे-जैसे फागुन की बयार तेज होती है और बाजारों में हलचल बढ़ती है, एक काला कारोबार भी अपनी जड़ें मजबूत करने लगता है। यह कारोबार है 'मिलावटी मावे' (खोया) का। राजधानी चौपाल की इस विशेष पड़ताल में हम उस कड़वी हकीकत से रूबरू होंगे, जो आपकी थाली में परोसी जाने वाली मिठास के पीछे छिपी है। हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक खाद्य सुरक्षा विभाग (FSDA) की ताबड़तोड़ छापेमारी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि मुनाफाखोरों के लिए इंसानी जान की कीमत चंद रुपयों से ज्यादा नहीं है। हजारों क्विंटल मिलावटी खोया जब्त किया जाना महज एक आंकड़ा नहीं, बल्कि हमारी सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए एक गंभीर चेतावनी है।

मिलावट का गणित: मांग और आपूर्ति का वह असंतुलन जो अपराध को जन्म देता है

भारत में डेयरी उत्पादों की खपत और उत्पादन के बीच एक बड़ा अंतराल है। विशेषकर होली, दिवाली और रक्षाबंधन जैसे त्योहारों पर मावे की मांग सामान्य दिनों के मुकाबले 400% तक बढ़ जाती है। दूध का उत्पादन रातों-रात नहीं बढ़ाया जा सकता, इसलिए इस 'शॉर्टेज' को भरने के लिए मिलावटखोर 'सिंथेटिक मावे' का सहारा लेते हैं। यह एक संगठित अपराध की तरह काम करता है, जहां ग्रामीण इलाकों की अवैध डेयरियों से नकली मावा तैयार कर शहरी बाजारों के थोक विक्रेताओं तक पहुंचाया जाता है। इस खेल में बिचौलिए और कुछ भ्रष्ट व्यापारी शामिल होते हैं जो जानते हैं कि आम आदमी शुद्धता और मिलावट के बारीक फर्क को नहीं समझ पाएगा।

जहरीली सामग्री का विश्लेषण: आखिर आपके मावे में क्या है?

मिलावटी खोया तैयार करने की प्रक्रिया किसी रासायनिक प्रयोगशाला से कम खौफनाक नहीं है। इसमें प्राकृतिक दूध का अंश नाममात्र का होता है।

- **सिंथेटिक दूध का आधार:** नकली खोया बनाने के लिए सबसे पहले यूरिया, कास्टिक सोडा और घटिया डिटर्जेंट मिलाकर कृत्रिम दूध तैयार किया जाता है। डिटर्जेंट झाग पैदा करता है और कास्टिक सोडा दूध को फटने से बचाता है।
- **फिलर्स और स्टार्च:** मावे को भारी बनाने और उसे बनावट (TEXTURE) देने के लिए उबले हुए घटिया आलू, शकरकंद और भारी मात्रा में मैदा या अरारोट मिलाया जाता है।
- **खतरनाक फैट:** दूध की प्राकृतिक चिकनाई (FAT) निकालने के बाद उसमें पाम ऑयल, वनस्पति घी या जानवरों की चर्बी मिला दी जाती है ताकि वह छूने में असली जैसा लगे।
- **सफेदी का भ्रम:** मावे को पुराना होने पर भी ताजा दिखाने के लिए ब्लीचिंग एजेंट और वाइटनर का उपयोग किया जाता है। ये रसायन सीधे तौर पर कार्सिनोजेनिक (कैंसरकारी) श्रेणी में आते हैं।

स्वास्थ्य पर वज्रपात: मिलावटी मावे के विनाशकारी परिणाम

चिकित्सा विशेषज्ञों का मानना है कि मिलावटी मावा केवल एक दिन की बीमारी नहीं, बल्कि जीवनभर का रोग दे सकता है।

- **गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डैमेज:** इसमें मौजूद डिटर्जेंट और यूरिया आंतों की म्यूकोसा परत को जला देते हैं। इससे तत्काल गंभीर पेट दर्द, खूनी दस्त और फूड पॉइजनिंग होती है।
- **लिवर और किडनी फेलियर:** किडनी का काम शरीर से विषाक्त पदार्थों को छानना है। जब हम रसायनों से युक्त मावा खाते हैं, तो किडनी पर अत्यधिक दबाव पड़ता है, जिससे 'नेफ्रोटिक सिंड्रोम' या किडनी फेलियर की स्थिति बन सकती है। इसी तरह लिवर में सूजन (Hepatotoxicity) पैदा हो जाती है।
- **हृदय और धमनियों पर प्रहार:** नकली मावे में मौजूद 'ट्रांस फैट्स' रक्त में बैड कोलेस्ट्रॉल (LDL) के स्तर को अचानक बढ़ा देते हैं। इससे धमनियों में प्लाक जमने लगता है, जो ब्लड प्रेशर बढ़ाता है और हार्ट अटैक का कारण बनता है।
- **बच्चों और बुजुर्गों के लिए घातक:** कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों के लिए यह 'मीठा जहर' जानलेवा साबित हो सकता है क्योंकि उनका शरीर इन रसायनों को झेलने में सक्षम नहीं होता।

शुद्धता की वैज्ञानिक जांच: 4 अचूक घरेलू तरीके

FSSAI (भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण) ने आम जनता के लिए कुछ सरल परीक्षण सुझाए हैं ताकि वे ठगी से बच सकें:

- **आयोडीन टेस्ट (स्टार्च की पहचान):** यह सबसे विश्वसनीय तरीका है। मावे के एक छोटे टुकड़े को पानी में घोलें और उसमें दो बूंद आयोडीन टिंचर डालें। यदि घोल का रंग गहरा नीला या काला हो जाए, तो इसमें आलू या मैदा मिला है। शुद्ध मावा अपना रंग नहीं बदलता।
- **हथेली घर्षण टेस्ट (फैट की जांच):** थोड़े से मावे को अपनी हथेली पर रखकर अंगूठे से रगड़ें। असली मावे से तुरंत घी की महक आएगी और हथेली चिकनी हो जाएगी। नकली मावे से रसायनों की गंध आएगी और वह रबर की तरह खिंचेगा।
- **चीनी दहन परीक्षण:** मावे में थोड़ी चीनी मिलाकर उसे कड़ाही में गर्म करें। असली मावा पिघलकर महकने लगेगा, जबकि मिलावटी मावा चिपचिपा हो जाएगा और पानी छोड़ देगा।
- **संवेदी जांच (स्वाद और महक):** असली खोया मुंह में नहीं चिपकता। यदि खाते समय यह दांतों में चिपक रहा है, तो इसमें मैदा है। यदि स्वाद तीखा या कड़वा है, तो इसमें डिटर्जेंट की मौजूदगी हो सकती है।

घर पर शुद्ध मावा बनाने की मुकम्मल विधि: परंपरा की ओर वापसी

बाजार के जोखिम को देखते हुए राजधानी चौपाल की सलाह है कि इस होली आप घर पर ही मावा तैयार करें।

- **सामग्री:** केवल शुद्ध फुल क्रीम दूध।
- **प्रक्रिया:** एक भारी तले की लोहे या स्टील की कड़ाही लें। दूध को तेज आंच पर उबालें और फिर आंच मध्यम कर दें। इसे लगातार चलाते रहें ताकि यह नीचे से जले नहीं। किनारों पर जमने वाली मलाई को खुरचकर वापस दूध में मिलाते रहें। जब दूध का सारा पानी सूख जाए और वह कड़ाही छोड़ने लगे, तो आपका शुद्ध मावा तैयार है। यह मावा न केवल सुरक्षित है, बल्कि आपकी मिठाइयों के स्वाद को चार गुना बढ़ा देगा।

होली का अमर पर्याय 'गुजिया' — परंपरा, स्वाद और मधुर महक...

भारतीय संस्कृति में त्योहारों का वास्तविक अर्थ केवल तिथियों के आगमन से नहीं, बल्कि उन विशिष्ट पकवानों से होता है जो रसोइयों में हफ्तों पहले बनने शुरू हो जाते हैं। जब हम फागुन के महीने और होली के हुड़दंग की चर्चा करते हैं, तो स्मृति पटल पर सबसे पहला नाम 'गुजिया' का उभरता है। उत्तर भारत की तंग गलियों से लेकर महानगरों के आलीशान डाइनिंग टेबल तक, गुजिया केवल एक मिठाई नहीं बल्कि प्रेम, उल्लास और भारतीय मेहमाननवाजी का जीवंत प्रतीक है। रसोई के खजाने की इस विशेष कड़ी में आज हम गुजिया के उस ऐतिहासिक और स्वाद भरे सफर का अन्वेषण करेंगे, जो इसके खस्ता आवरण से शुरू होकर मावे की अद्भुत मिठास पर समाप्त होता है।

गुजिया का ऐतिहासिक विकास: मध्य एशिया से ब्रज के आंगन तक

गुजिया का इतिहास अत्यंत प्राचीन और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है। कई खाद्य इतिहासकारों का यह मत है कि गुजिया का मूल स्वरूप 'समोसे' के विकासक्रम से प्रेरित है, जिसे 13वीं शताब्दी के आसपास मध्य पूर्व से भारत लाया गया था। हालांकि, भारत की रसोइयों ने अपनी रचनात्मकता से इसे पूरी तरह भारतीय परिवेश में ढाल दिया। नमकीन समोसे के जवाब में तैयार किया गया यह मीठा पकवान विशेष रूप से ब्रज क्षेत्र में लोकप्रिय हुआ। भगवान कृष्ण की नगरी में होली के अवसर पर गुजिया का भोग लगाना एक अनिवार्य परंपरा बन गई। धीरे-धीरे राजस्थान और उत्तर प्रदेश के घरों में इसे बनाने की रस्म एक सामुदायिक उत्सव में तब्दील हो गई, जहाँ परिवार की सभी पीढ़ियाँ मिलकर इसे आकार देती हैं।

पाक विज्ञान का समन्वय: बनावट और भरावन का सटीक संतुलन

एक आदर्श गुजिया तैयार करने के पीछे एक सूक्ष्म वैज्ञानिक प्रक्रिया काम करती है। इसे मुख्य रूप से दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है—मैदे का आवरण और आंतरिक भरावन। गुजिया का बाहरी हिस्सा जिसे 'क्रस्ट' कहा जाता है, उसे खस्ता बनाने के लिए 'मोयन' का सही अनुपात अत्यंत आवश्यक है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो आटे में घी मिलाने से वह आटे के ग्लूटेन स्ट्रक्चर को संशोधित कर देता है, जिससे पकने के बाद वह सख्त होने के बजाय कुरकुरा और परतदार बनता है। आम तौर पर एक किलो मैदा में लगभग दो सौ से ढाई सौ ग्राम शुद्ध घी का मोयन श्रेष्ठ माना जाता है। इसी प्रकार, इसके अंदर भरा जाने वाला मावा, सूजी और सूखे मेवे का मिश्रण इसके स्वाद की आत्मा है।

परंपरागत मावा गुजिया की मास्टर रेसिपी: रसोई की कला

रसोई के खजाने की प्रामाणिक विधि के अनुसार, गुजिया बनाने के लिए धैर्य और गुणवत्तापूर्ण सामग्री का होना अनिवार्य है। सबसे पहले आधा किलो मैदा में शुद्ध घी का मोयन डालकर उसे ठंडे पानी या दूध की सहायता से सख्त गूंथ लिया जाता है। इस आटे को कम से कम आधे घंटे के लिए गीले कपड़े से ढककर रखना जरूरी है ताकि ग्लूटेन सक्रिय हो सके। भरावन तैयार करने के लिए ताजे मावे को मध्यम आंच पर गुलाबी होने तक भूना जाता है, जिससे इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। इसमें बारीक भुनी हुई सूजी, पीसी हुई चीनी, इलायची पाउडर और कतरे हुए सूखे मेवे जैसे बादाम, काजू और किशमिश मिलाए जाते हैं। फिर छोटी-छोटी लोइयां बेलकर सांचों की मदद से उन्हें भरा जाता है और मध्यम गर्म घी में सुनहरा होने तक तला जाता है।

क्षेत्रीय विविधताएं: भारत के हर कोने में गुजिया का अलग रंग

गुजिया भारत के भौगोलिक विस्तार के साथ अपने नाम और स्वरूप बदलती रहती है। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसका एक राजसी रूप 'चंद्रकला' के नाम से प्रसिद्ध है, जो गोल होती है और तलने के बाद इसे गाढ़ी चाशनी में डुबोया जाता है। वहीं महाराष्ट्र में इसे 'करंजी' के रूप में जाना जाता है, जहाँ भरावन में मावे के स्थान पर सूखे नारियल और खसखस का अधिक प्रयोग किया जाता है। गोवा के तटीय क्षेत्रों में क्रिसमस और गणेश चतुर्थी के दौरान 'नेवरे' बनाए जाते हैं, जिनमें गुड़ और ताजे नारियल की मिठास प्रमुख होती है। दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में इसे 'सोमसा' कहा जाता है, जहाँ चने की दाल और गुड़ का मिश्रण इसके स्वाद को एक अनूठा मोड़ देता है।

आधुनिक दौर के बदलाव: स्वास्थ्य और फ्यूजन का मेल

बदलते समय और स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरूकता ने गुजिया के पारंपरिक स्वरूप में भी नवीनता ला दी है। आजकल 'बेक्ड गुजिया' का प्रचलन काफी बढ़ा है, जो उन लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प है जो तेल और घी के अत्यधिक सेवन से बचना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त, युवा पीढ़ी को आकर्षित करने के लिए अब चॉकलेट गुजिया, ओट्स गुजिया और अंजीर-खजूर के मिश्रण वाली शुगर-फ्री गुजिया भी रसोइयों में जगह बना रही हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि हमारी परंपराएं जड़ नहीं हैं, बल्कि वे समय के साथ विकसित होने की क्षमता रखती हैं। लोग अब मैदे की जगह गेहूं के आटे या मल्टीग्रेन आटे का प्रयोग करके इसे और अधिक पौष्टिक बनाने के प्रयास कर रहे हैं।

शुद्धता की चुनौती: त्यौहारों के दौरान सावधानी और सतर्कता

होली के त्यौहार पर बाजार में मिलावट का खतरा सबसे अधिक होता है, इसलिए अपनी रसोई में शुद्धता सुनिश्चित करना सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। नकली मावे में मौजूद यूरिया, डिटर्जेंट और खतरनाक फैट आपकी खुशियों को बीमारी में बदल सकते हैं। रसोई के खजाने की सलाह है कि सदैव प्रतिष्ठित डेयरी से ही सामग्री खरीदें या घर पर ही दूध जलाकर खोया तैयार करें। यदि बाजार से मावा ला रहे हैं, तो आयोडीन परीक्षण के माध्यम से उसकी जांच अवश्य करें। मावे का रंग बहुत ज्यादा सफेद होना मिलावट का संकेत हो सकता है, क्योंकि शुद्ध मावा हल्का मटमैला या क्रीम रंग का होता है।

संरक्षण और समापन: यादों और मिठास को संजोना

गुजिया को लंबे समय तक ताजा रखने के लिए कुछ जरूरी सावधानियां बरतनी चाहिए। तलने के बाद गुजिया को तुरंत डिब्बे में बंद नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें पूरी तरह ठंडा होने देना चाहिए ताकि भाप से वे नरम न पड़ें। मावे वाली गुजिया को दस से बारह दिनों के भीतर उपयोग कर लेना चाहिए, जबकि सूजी और नारियल वाली गुजिया अधिक समय तक सुरक्षित रखी जा सकती हैं। अंततः, गुजिया बनाना केवल एक पाक क्रिया नहीं है, बल्कि यह रिश्तों को सींचने का एक माध्यम है।

भारत फिर बढ़ाएगा रूस से कच्चे तेल की खरीद

95 लाख बैरल तेल पर नजर; ईरान-इजराइल जंग के बीच स्ट्रैट ऑफ होर्मुज से सप्लाई रुकी

नई दिल्ली| मिडिल ईस्ट में ईरान-इजराइल के बीच जंग और तेल की सप्लाई चैन प्रभावित होने के बाद भारत ने एक बार फिर रूस की ओर रुख किया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए रूस से कच्चे तेल की खरीद बढ़ाने का प्लान बना रहा है। पिछले कुछ दिनों में स्ट्रैट ऑफ होर्मुज के जरिए होने वाली तेल की सप्लाई लगभग ठप हो गई है, जिसके चलते सरकारी रिफाइनरीज और पेट्रोलियम मंत्रालय के अधिकारियों ने दिल्ली में एक इमरजेंसी मीटिंग कर विकल्प तलाशने शुरू कर दिए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, भारत उन रूसी तेल कार्गो को खरीदने पर विचार कर रहा है, जो फिलहाल भारतीय समुद्र के करीब या एशियाई जल क्षेत्र में मौजूद हैं। आंकड़ों के मुताबिक, इस समय लगभग 95 लाख बैरल रूसी कच्चा तेल टैंकरों में भरकर एशियाई देशों के आसपास वेटिंग मोड में है। सप्लाई में कमी आने की स्थिति में भारत इन टैंकरों को तुरंत रिसीव कर सकता है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन का समय और लागत दोनों कम होगी।

अमेरिकी दबाव और प्रतिबंधों की सख्ती के कारण भारत ने पिछले कुछ महीनों में रूस से तेल की खरीद कम कर दी थी। फरवरी में भारत ने रूस से प्रतिदिन केवल 10 लाख बैरल तेल खरीदा, जो सितंबर 2022 के बाद का सबसे निचला स्तर है।

RNI No. HARHIN/25/A3341, प्रकाशक, मुद्रक स्वामी एवं संपादक राहुल कुमार द्वारा सूचना प्रिंटर्स 33एस मॉडल टाउन, हिसार से छपवाकर कार्यालय आदमपुर मंडी हिसार, (किसी भी विवाद का न्याय क्षेत्र हिसार न्यायालय होगा)।
संपादक : राहुल कुमार, फोन : 9306813001, e-mail : rajdhanichoupal@gmail.com, प्रकाशन स्थल : मकान संख्या : 114, शांति पार्क के पास, मंडी आदमपुर, हिसार (हरियाणा)